● वर्ष-5

● अंक-301

रायपुर, मंगलवार
04 अगस्त 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर...

संसद में पेपर लीक-चढ़ावा चोरी पर नहीं थमा घमासान

अमित शाह के जवाब पर अड़ा विपक्ष

नईदिल्ली। मानसून सत्र के कुल 25 दिनों में से 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब दोनों सदनों की कार्यवाही बिना रोक-टोक के चल पाई हो। सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि, शोर-शराबे के बीच दोनों सदनों में अहम विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गए।लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कार्यवाही महज 3 मिनट बाद स्थगित हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जताई और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदस्यों से जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा, लेकिन

विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। इसी दौरान भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश किया गया।इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 सदन में पेश किया। हालांकि, विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर-शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी

दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी करते रहे।हंगामे के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में भी हंगामा

राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शांत रहने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन शोर-शराबा जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 विचार के लिए सदन में रखा।

सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी।हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहता।

शोर-शराबे के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में अब 38 हो जाएगी जजों की संख्या... लोकसभा से बिल पास

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक और राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा में एक बिल बिना बहस के पास हो गया। यह बिल उस अध्यादेश की जगह लेने के लिए था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी।

वहीं, विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के सदस्यों द्वारा अध्यादेश जारी करने की निंदा करते हुए पेश किए गए एक वैधानिक प्रस्ताव को भी ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की संक्षिप्त शुरुआती टिप्पणी के बाद पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से वैधानिक प्रस्ताव पर बोलने का आग्रह किया लेकिन नारेबाजी जारी रहने के कारण बिल को मतदान के लिए रखा गया और बाद में पारित कर दिया गया।

जंतर-मंतर प्रदर्शन; सरकार ने कहा

छात्रों पर केस नहीं होगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हृश्वश्वञ्ज पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा, 'सरकार अपने वादे पर कायम है। छात्रों के खिलाफ कोई स्नङ्कक नहीं होगी।'मेहता ने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों को लेकर जिन 2700 से ज्यादा लोगों पर स्नङ्कक दर्ज हुई हैं, इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा।

कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मसले पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी 3 मांगें थी, जो सरकार ने मान ली थीं। इनमें एक मांग यह भी थी कि सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। मामले पर अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया गया है। वकील वृंदा ग्रोवर ने पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों

के खिलाफ दर्ज स्नङ्कक वापस ली जाएंगी या रद्द की जाएंगी। इस पर मेहता ने कहा कि कानूनी तौर पर जो भी तरीका सही हो, सरकार अपने वादे पर कायम है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करता है, तो उसे बेवजह बचाया नहीं जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में किसी कुख्यात अपराधी को बचाया जाए।

परीक्षाओं में गड़बड़ी और हृश्वश्वञ्ज पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 36 दिन तक चला था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह प्रदर्शन खत्म कर दिया गया था।

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भगवान शिव की भक्ति एवं आराधना को समर्पित पावन श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं दी हैं।

2000 युवाओं को संबोधित करेंगे मोहन

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद आज की 'जेन जी' जनरेशन की बात हर तरफ हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अब लद्दठ्ठ को साधने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी तैयारी की दिशा में आरएसएस चीफ मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में आयोजित होने वाले एक यूथ कार्यक्रम में 2000 के करीब बच्चों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक शहरों के टीनएजर्स शामिल होंगे।

यह कार्यक्रम मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित होगा जहां वे जेन-जीऔर जेन-अल्फा जनरेशन के छात्रों के साथ लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 15 से 19 साल के बच्चे शामिल होंगे। यह कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं सालगिरह के मौके

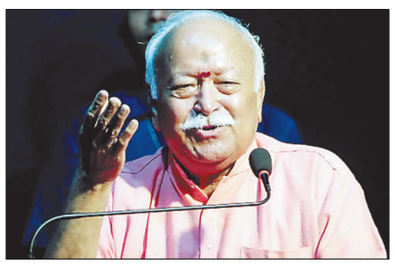

पर आयोजित होगा।

इस सम्मेलन की थीम The Role of Youth in Uniting the World, the Indian Way रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल और सिविक मुद्दों पर बहस करेंगे। ऑर्गनाइजर ने कहा कि यह इवेंट ऐसे समय में हो रहा है जब युवा लोग लीडरशिप, डेमोक्रेसी और देश बनाने के बारे में बातचीत को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं।

मोहन भागवत का यह संबोधन टीनएजर्स तक संघ की पहुंच को ले जाने का प्रयास भी होगा। पीएम मोदी के बाद संघ की ओर से की जा रही इस पहल का फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को भी होगा। यह बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हाल के महीनों में जेन-जी स्टूडेंट्स के साथ भागवत की सबसे बड़ी मुलाकातों में से एक होगी, जो एग्जाम पेपर लीक पर युवाओं की अगुवाई में हुई लामबंदी के कुछ दिनों बाद हो रही है। जिसने युवा वोटरों और स्टूडेंट एक्टिविज्म को नेशनल लाइमलाइट में ला दिया था।

आईआईएमयूएन की स्थापना 2011 में ऋषभ शाह ने की थी। संगठन का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और भारत के विचारों के माध्यम से वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है।

नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीते

नईदिल्ली। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को हुए उपचुनावों की मतगणना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दतिया में कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हराया है। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। वे लगभग 49 प्रतिशत वोट हासिल कर चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 34 प्रतिशत वोट ही मिला है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 32 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर को बड़ी जीत हासिल हुई है। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को बड़े मार्जिन से हराया है। इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने पर खाली हुई थी, और बीजेपी यहां बड़ी जीत की उम्मीद कर रही थी।

मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करारी शिकस्त दी है। उन्हें कुल 66,757 वोट मिले।

प्रमुख समाचार

दोनों सदनों में पदकवीर खिलाड़ियों को दी गई बधाई

नयी दिल्ली। ग्लासगो में संपन्न 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सोमवार को संसद के दोनों सदनों में बधाई दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले

हर्ष सिंह, अस्मिता डे, जैसमीन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरूंधति चौधरी, प्रिया घंघास, सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल तथा पैरा एथलीट सोमन राणा का उल्लेख किया। बिरला ने रजत पदक विजेता खिलाड़ियों प्रवीण चित्रावेल, यामिनी मौर्य, जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा और पैराएथलीट शुभम जुआल का भी नाम लिया। राज्यसभा में सभापति सी पी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है।

केजरीवाल ई20 पेट्रोल के विरोध में पीएम आवास तक मार्च करेंगे

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे और ई20 ईंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इसे बढ़ावा दे रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने ''घुटने टेक दिए'' हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लगातार बढ़ावा देना किसी ''छिपे हुए एजेंडे'' का संकेत है। केजरीवाल ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मैं मंगलवार को 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर जनता द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से सौंपूंगा और इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करूंगा। लोगों को अपनी गाड़ियों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

लखनऊ में नीट पेपर लीक को लेकर सपा का प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने विधान भवन परिसर में अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बड़ी संख्या में सपा सदस्यों ने तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी, पिछले दस वर्षों में प्रदेश में 26 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय बंद किए जाने, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का प्रश्नपत्र लीक होने, कानून-व्यवस्था की कथित बदहाली तथा अन्य जनसरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। कुछ सदस्यों ने विरोध के प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर पर 'चंदा पेटिका' लिखे दानपात्र भी रखे थे। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की ''डबल इंजन'' सरकार ने प्रदेश को ऐसा तोहफा दिया है।

सीएम योगी ने सपा के दोहरे रवैये पर बोला हमला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदे के प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग यह मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने पहले मंदिर निर्माण का विरोध किया था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का मुद्दा उन लोगों द्वारा उठाया जा रहा है जिन्होंने पहले विरोध प्रदर्शनों के दौरान राम भक्तों के खिलाफ कार्रवाई की थी। योगी ने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि अयोध्या का मुद्दा वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थीं। ये वही लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा लेते थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो लोग मंदिर के दान के प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने पहले कानूनी अड़चनें डालकर राम मंदिर के निर्माण में देरी करने की कोशिश की थी।

संसद परिसर में पप्पू यादव ने जो किया गलत था : रामगोपाल

नईदिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सोमवार को सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद समेत विपक्ष के नेताओं के खिलाफ

एफआईआर दर्ज की है। मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि सरकार का ध्यान नैरेटिव बनाने और दोष दूसरों पर मढ़ने पर है। राम गोपाल ने कहा कि यह गलत था, क्योंकि राम मंदिर में हुई चोरी से संतों का कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, असल में यह एक गलत काम था; ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार खुद ही रचनात्मक काम नहीं करती, तो रचनात्मक अभिव्यक्ति के उभरने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके बजाय, वे एक नैरेटिव बनाने, तथ्यों को घुमाने-फिराने और दूसरों पर दोष मढ़ने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। वे इसमें माहिर हैं। ये बातें मंत्री ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणियों के बाद सामने आई, जिन्होंने संसद परिसर में राम मंदिर स्किट की घटना पर समाजवादी पार्टी के रुख पर सवाल उठाए।

आंदोलन की संस्कृतिः अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी आवश्यक

ललित गर्ग

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हाल के वर्षों में कुछ आंदोलनों ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य हो सकता है? यदि कोई प्रदर्शन बैरिकेड तोड़ने, पुलिस पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान की ओर जबरन बढ़ने का प्रयास करे, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे केवल मूकदर्शक बनी रहें। राज्य का पहला दायित्व नागरिकों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए यह कहना कि असाधारण परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसी संतुलित दृष्टिकोण का परिचायक है। न्यायालय ने किसी भी प्रकार के असीमित बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया, बल्कि यह स्पष्ट संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पास आवश्यक साधन भी होने चाहिए। यदि सुरक्षा बलों से हर प्रभावी उपाय छीन लिया जाएगा, तो हिंसक भीड़ पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल जाने चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही के दायरे में रहती है। यदि कहीं बल प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर

कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जांच का आधार तथ्य होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं। जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों की पीड़ा सुनी जानी चाहिए, उसी प्रकार घायल हुए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों का पक्ष भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं। दुर्भाग्य से आज कुछ आंदोलनों में संवाद की जगह टकराव, संयम की जगह उग्रता और तर्क की जगह भीड़ की शक्ति को महत्व दिया जाने लगा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में परिवर्तन सड़क पर पत्थर फेंकने से नहीं, बल्कि विचार, संगठन, जनजागरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आता है। यदि हर असहमति हिंसक रूप ले लेगी, तो सबसे अधिक नुकसान उन्हीं युवाओं का होगा, जिनके भविष्य के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व से होती है।

यदि यह मान लिया जाए कि किसी राजनीतिक दल या उसके समर्थकों द्वारा आयोजित आंदोलन में कुछ असामाजिक और हिंसक तत्वों ने प्रवेश कर उसे अराजक दिशा देने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्राथमिक दायित्व कानून-व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। समय रहते प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, भले ही उससे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हों, व्यापक अराजकता और राष्ट्रीय संस्थानों को संभावित क्षति से बचाने के उद्देश्य से देखी जा सकती है। साथ ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह भी अपेक्षित है कि विपक्ष जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंसा और तोड़फोड़ से स्पष्ट दूरी बनाए तथा वैध मांगों के समर्थन और अवैध कृत्यों के विरोध के बीच स्पष्ट रेखा खींचे। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होता है जब सरकार कानून के शासन का पालन करे, विपक्ष जिम्मेदार आचरण करे और आंदोलन संविधान की मर्यादाओं एवं शांतिपूर्ण तरीकों के भीतर संचालित हों।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी दल का यह दायित्व है कि वह जनभावनाओं को सकारात्मक दिशा दे। यदि कोई राजनीतिक संगठन या उसके समर्थक आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ या कानून हाथ में लेने को प्रोत्साहित करते हैं।

श्रावण के पहले सोमवार में बहा अस्था और भरोसे का सैलाब, रास्तो पर दिखे कांवड यात्री

मां दंतेश्वरी के दर्शन बाद भैरव बाबा के भक्त कर रहे दर्शन, मांग रहे शिव से मनोकामना

दंतेवाड़ा। श्रावण सोमवार के पहले दिन मां दंतेश्वरी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दरबार में भक्त पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली जो दोपहर बाद तक जारी रही। छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों से पहुंचे हजारों भक्तों ने विधि-विधान से मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और इसके बाद मंदिर परिसर के पीछे स्थित भैरव बाबा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। मान्यता है कि मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर यहां श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिर में सुबह से ही जय मां दंतेश्वरी और हर-हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं। भक्तों ने माता को नारियल, चुनरी, फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली

की कामना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक शक्तिपीठ में भैरव बाबा का विशेष स्थान होता है। उन्होंने बताया कि मां दंतेश्वरी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना होता है, इसलिए इस माह में माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना शक्तिपीठ की यात्रा पूर्ण नहीं होती। मंदिर के पुजारी की मानें तो धार्मिक मान्यताओं में भैरव बाबा को शक्तिपीठों का रक्षक और क्षेत्रपाल माना गया है। इसलिए मां दंतेश्वरी के दर्शन के पश्चात श्रद्धालु भैरव बाबा के चरणों में शीश नवाकर अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन सोमवार के अवसर पर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मां दंतेश्वरी और भैरव बाबा की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं।

गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब

गरियाबंद। सावन के पहले सोमवार पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्थित विश्व के विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वरनाथ महादेव के दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पवित्र नदियों का जल, दूध, बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर पहुंचे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में आज भक्तों की संख्या लगभग दोगुनी नजर आ रही है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में माने जाने वाले भूतेश्वरनाथ महादेव में सावन का प्रथम सोमवार खास महत्व रखता है। नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर दूर से कई कांवरिये यहां पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रदेश सहित ओडिशा और बाकी राज्यों से आए श्रद्धालु जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना में जुटे हैं।यहां कि मान्यता है कि यह शिवलिंग हर साल लंबाई और चौड़ाई में बढ़ता जा रहा है। बाबा भूतेश्वरनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। यही कारण है कि दूर-दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। समिति के सदस्यों ने इस बार पहले से बेहतर व्यवस्था की है।

कांवड़ यात्रा निकालकर रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव का अभिषेक

धमतरी। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बोल बम कांवरिया कल्याण संघ की ओर से लगातार 33 साल से आयोजित हो रही पारंपरिक कांवड़ यात्रा में शिवभक्त उमड़ पड़े। तीन दशक से भी अधिक समय से चली आ रही ये धार्मिक परंपरा इस बार भी हर्षोल्लास से निभाई गई।श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कांवड़ यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाएं, बच्चे, युवतियों ने भी हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत रुद्री स्थित प्रसिद्ध रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से हुई। यहां सबसे पहले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधिवत पूजन-अर्चन और जलाभिषेक किया। इसके बाद महानदी के पवित्र तट से कांवड़ में जल भरकर श्रद्धालु हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ शहर की ओर रवाना हुए। पूरे मार्ग में शिवभक्ति का माहौल देखते ही बन रहा था।कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख

मार्गों से होकर निकली। रास्ते भर श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे। कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। फल और प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने भी सेवा करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्कूल में शराब पार्टी पड़ी भारीः दोनों शिक्षक निलंबित

गरियाबंद। जिले में शिक्षा विभाग बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मैनपुर विकासखंड के देवझर (अमली) स्कूल में शराब पार्टी करने वाले दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मैनपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) के दो शिक्षक मनोज कुमार भारद्वाज और कमल सिंह दीवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों शिक्षक स्कूल कार्यालय में ही शराब पीते और चखना खाते दिखाई दिए थे। इस दौरान कई छात्र-छात्राएं बिना पढ़ाई के स्कूल परिसर में मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर ने दोनों शिक्षकों के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले मामले में दोनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। विभागीय स्तर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए अब निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश के अनुसार, दोनों शिक्षकों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। मामले की विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी। जांच रिपोर्ट और नियमानुसार प्रक्रिया के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तुमलपाड़ में खनन के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

सुकमा में सिलगेर एल्मागुंडा सड़क निर्माण के लिए खनन के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए है.

सुकमा। सिलगेर एल्मागुंडा सड़क निर्माण परियोजना के तहत तुमलपाड़ गांव के समीप संचालित खदान और दो बड़े क्रेशर प्लांटों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़क निर्माण या विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े पहाड़ पर बिना विधिवत ग्रामसभा की सहमति के खनन किया जाना उनके अधिकारों और विश्वास की अनदेखी है।

रविवार को पूर्व विधायक एवं आदिवासी नेता मनीष कुंजाम गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। ग्रामीणों ने एक स्वर में क्रेशर प्लांट बंद कराने और खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि कंपनी ने गांव के विकास के नाम पर कई बड़े वादे किए थे, लेकिन चार महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एक भी वादा धरातल पर नजर नहीं आया। ग्रामीणों से चर्चा के बाद मनीष कुंजाम ने कहा कि क्षेत्र के लोग विकास विरोधी नहीं हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हर गांव तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर यदि ग्रामसभा की सहमति, आदिवासी परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की जाएगी तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है।उनका आरोप है कि पहले ग्रामीणों ने पहाड़ पर खनन की अनुमति देने से साफ इनकार किया था, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के दबाव और विकास कार्यों के आश्वासन देकर प्रस्ताव लिया गया। गांव के सरपंच इरपा किष्टैया ने भी बताया कि शुरू में ग्रामीण खनन के पक्ष में नहीं थे। बाद में गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, नलकूप, सड़क, खेतों की जुताई और अन्य विकास कार्य कराने के आश्वासन दिए गए, जिसके बाद प्रस्ताव दिया गया।

वहीं ग्रामसभा की अध्यक्षता करने वाले कुहराम जोगा का कहना है कि खदान के संबंध में विधिवत ग्रामसभा आयोजित ही नहीं हुई और अधिकांश ग्रामीण शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब खनन कार्य का सबसे ज्यादा असर उनकी खेती और आजीविका पर पड़ रहा है। ग्रामीण रमेश सोयम, सोयम एंका, सोढ़ी मंगो, माड़वी हांदा और माड़वी नंदा ने बताया कि उनके खेत पहाड़ के बिल्कुल समीप स्थित हैं।

बदमाशों ने सरपंच की चाकू से हत्या कर मोबाइल और कैश लूटकर हुए फरार

दुर्ग। ग्राम तूमाकला के उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की चाकू से गोदकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना रविवार देर रात करगीडीह से चिखली चौक के बीच उस समय हुई, जब प्रकाश सिंह कश्यप अपने एक साथी के साथ भिलाई से वापस गांव लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार लूट का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र का है।

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि रास्ते में एक बाइक पर सवार चार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने पहले मोबाइल फोन और नकदी लूटने की कोशिश की। जब प्रकाश सिंह कश्यप ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के दौरान उनके साथ मौजूद व्यक्ति किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और पुलिस को सूचना दी।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रकाश सिंह कश्यप का मोबाइल फोन और करीब चार हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही जेवरा-सिरसा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मृतक प्रकाश सिंह कश्यप धमधा ब्लॉक के ग्राम तुमाकला के उपसरपंच थे। उनकी पत्नी देवती बाई कश्यप वर्तमान में गांव की सरपंच है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। सीएसपी ने बताया, शुरुआती जांच में मामला लूट के दौरान हत्या का प्रतीत हो रहा है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।

प्रदेशभर के पटवारी हड़ताल पर, पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की उठाई मांग

बलौदाबाजार। दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेशभर के पटवारी एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पटवारी भी अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में प्रदर्शन कर शासन से राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति व परीक्षा के माध्यम से 50-50 प्रतिशत स्थान देने, साथ ही वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे।

पटवारी संघ के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की बहुत कमी है। हमारी मांग है कि वरिष्ठता एवं विभागीय परीक्षा के आधार पर हमें प्राथमिकता दी जाए। सन 2013 के बाद से आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। साथ ही वेतन में विसंगति है, जिसे दूर किया जाए। आज हमने एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। मांग पूरी नहीं होती है तो प्रांत स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राजस्व पटवारियों का अल्टीमेट मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर सोमवार को दंतेवाड़ा में जिला इकाई के पटवारियों ने दुर्गा मंच पर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन कर अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। पटवारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, जिसका सीधा असर राजस्व कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। पटवारी संघ की प्रमुख मांग पदोन्नति व्यवस्था में सुधार को लेकर है। संघ का कहना है कि वर्तमान में पटवारियों की पदोन्नति के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है।इसके कारण कई कर्मचारी पूरी सेवा अवधि पटवारी पद पर ही कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

एसआई के बेटे पर जान से मारने की धमकी व लूट का आरोप

बिलासपुर। राजीव विहार के रहने वाले रहने वाले देवी प्रसाद सिंह का आरोप है कि उनकी नाबालिग पोती से कुछ लोगों ने दोस्ती की और फिर घर के दूसरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हुए कैश और सोने के जेवर मिलाकर लगभग 1 से सवा करोड़ रुपये हड़प लिए। उन्होंने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की है। देवी प्रसाद सिंह ने बताया कि नाबालिग पोती से दोस्ती करके फर्जी गैंग ने हाल ही में एटीएम से पैसे निकालने गई बच्ची को डरा धमकाकर 5000 रुपये छीन लिए। और साथ में गई 6 साल की पोती के गले में चाकू रखकर लाखों रुपये की डिमांड की। साथ ही धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता देवी प्रसाद ने बताया कि आरोपी का नाम आयुष यादव है जो सीपत में एसआई का बेटा है। जनवरी 2025 से वह उनकी नाबालिग पोती को परेशान कर लाखों रुपये हड़प चुका है। पीड़ित ने ये भी बताया कि आरोपी ने खुद उनकी पोती को बताया था कि मई में उनकी दादी का एक्सीडेंट भी उसी ने ही कराया था।

रामानुजगंज इंटरस्टेट चेकपोस्ट की सड़क बदहाल, राहगीर की बढ़ी चिंता

बलरामपुर रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ने वाले कन्हर बेरियर पर बड़े गड्ढे से लोग परेशान हैं। ये गहरे गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। इस चेकपोस्ट के रास्ते से रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहनों का आना जाना होता है। कन्हर पुल से पहले चेकपोस्ट पर निर्मित ये गड्ढे दुर्घटना की वजह भी बन रहे हैं। बलरामपुर रामानुजगंज स्थित इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन चुके हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भरा हुआ रहता है। वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जर्जर सड़क के गड्ढों की वजह से वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। साथ ही वाहनों में भी टूट फुट और क्षति हो रही है। इस संबंध में स्थानीय युवा और इस रास्ते से हर दिन आवाजाही करने वाले प्रदीप कश्यप ने कहा कि यहां छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर सड़क बहुत खराब है। जिसकी वजह से इस रास्ते से आने जाने में काफी कठिनाई होती है। गाड़ी को नुकसान भी होता है साथ ही यहां हमेशा जाम भी लगा रहता है।

आतंकी हमले में मारे गए मजदूर के परिवार से मिले कांग्रेस नेता

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम छुईहा निवासी भूपेंद्र भैना के परिवार का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है. घटना के तीन दिन बाद भी परिजनों का दावा है कि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है। ऐसे में परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों संकटों से गुजर रहा है। वहीं दूसरी ओर परिवार को सांत्वना देने नेताओं और जनप्रतिनिधियों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन पर परिजनों से बात कर गहरा शोक व्यक्त किया और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मृतक भूपेंद्र भैना की बहन अन्नू ने बताया कि परिवार को अपने भाई के अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनका तीन वर्षीय भतीजा मानस भी अपने पिता को आखिरी बार नहीं देख सका। इस मौके पर परिवार का दुख साझा करने पूर्व संसदीय सचिव चंद्रदेव राय भी पहुंचे।

सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ एमसीबी जिला

कोरिया/एमसीबी। सावन माह के प्रथम सोमवार पर पूरा कोरिया और एमसीबी जिला शिवभक्ति में सराबोर नजर आया। सुबह से ही जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर-हर महादेव के जयघोष, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं पंचामृत अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। बैकुंठपुर में सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर महिलाओं ने हरे रंग की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर सामूहिक जलाभिषेक यात्रा निकाली। सभी महिलाएं नदी तट स्थित हनुमान टेकरी में एकत्रित हुईं और वहां से नाका स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूरे मार्ग में हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बैकुंठपुर के प्रेमाबाग शिव मंदिर प्रांगण में देवरहा बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ।

केबल चोरों को ग्रामीणों ने दी सजा

रस्सी से बांधकर पीटा, फिर किया पुलिस के हवाल

कोरबा। कोरबा में दो चोर मोबाइल टावर की केबल काटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। लोगों ने उन दोनों को रस्सी से बांधकर पहले जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दावा किया जा रहा है कि जिले में 3 महीने में 33 टावरों में चोरी की घटनाएं हुई है। वहीं दो चोर जब सीतामणी स्थित राम मंदिर परिसर में लगे मोबाइल टावर की केबल काट रहे थे, तो उन्हें स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

इसके बाद उन्होंने दोनों को रस्सी से बांध दिया और जमकर पीटा। पिटाई के बाद इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिल ने दोनों आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया।

स्थानीय लोगों ने पकड़े गए युवकों के नाम एकलाख खान और लक्की बताया है। लोगों का आरोप है कि दोनों नशे की हालत में थे।

उनके पास से गांजा, चिलम और नशीले इंजेक्शन की शीशियां भी मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

कांग्रेस नेत्री रीता सिंह और उनके परिवार पर करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का केस

25 एकड़ जमीन की सौदेबाजी का मामला, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

दुर्ग। जिले में करोड़ों रुपए की जमीन के सौदे को लेकर कांग्रेस नेत्री रीता सिंह पर स्रढ्ढक दर्ज की गई है। रीता सिंह भिलाई नगर निगम की एमआईसी सदस्य हैं। कोर्ट के आदेश के बाद रीता सिंह के साथ उनके पति रमेश चंद्र सिंह और बेटे मानवचंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पाटन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय के आदेश के बाद उतई पुलिस ने की है। मामले की शिकायत रायपुर निवासी बीपी सिंह ने निजी परिवाद के माध्यम से कोर्ट में की थी। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में छांटा स्थित गिट्टी खदान और उससे लगी करीब 25 एकड़ जमीन का सौदा 4 करोड़ 50 लाख रुपये में तय हुआ था। इस सौदे में एक चेन मशीन और दो हाइवा वाहन भी शामिल थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सौदे के दौरान बताया गया कि 13 एकड़

जमीन आरोपियों के नाम है, जबकि 7 एकड़ दान की जमीन और 5 एकड़ सरकारी लीज की जमीन भी सौदे में शामिल कर दी गई। बीपी सिंह का आरोप है कि दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि जमीन बेचने का दावा करने वाले वास्तविक मालिक नहीं थे। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी इकरारनामा और अन्य दस्तावेज तैयार किए। असली भू-स्वामियों की जगह दूसरे लोगों के हस्ताक्षर कराए और गलत जानकारी देकर करोड़ों रुपये का सौदा किया। शिकायत के अनुसार, सौदे के लिए कुल 4 करोड़ 39 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए गए। इनमें 2 करोड़ 90 लाख रुपये मानवचंद सिंह, 1 करोड़ रुपये रीता सिंह और शेष राशि रमेश चंद्र सिंह के खाते में जमा कराई गई। आरोप है कि भुगतान के बावजूद केवल 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि शेष जमीन का नामांतरण और अन्य शर्तें पूरी नहीं की गईं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला मानते हुए उतई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को 15 दिनों के भीतर स्रढ्ढकऔर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। पुलिस अब दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और जमीन के स्वामित्व से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट में डीजीपी का हलफनामा

जांच पूरी, लेकिन 1.45 लाख मामलों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं

बिलासपुर।प्रदेशभर के पुलिस थानों में जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 1 लाख 45 हजार से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं, जिनकी क्लोजर रिपोर्ट अभी तक हाईकोर्ट में पेश नहीं की गई। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीपी ने एफिडेविट के साथ इस तथ्यात्मक विवरण को हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया था। बताया गया कि बीते 20 मई से 16 जुलाई तक सिर्फ 2 हजार 617 मामलों में ही खात्मा रिपोर्ट पेश की गई है। बता दें, कि याचिकाकर्ता योगेश बाबू शर्मा की अलग-अलग याचिका पर बीते दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल और 5 मई को आदेश जारी कर डीजीपी से शपथ पत्र में जवाब तलब किया था। मामले में आगामी सुनवाई 18 अगस्त तय की गई है।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय वन सेवा के पांच प्रशिक्षुकों को मिली पदस्थापना

रायपुर। राज्य शासन ने वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा के पांच प्रशिक्षु अधिकारियों को उनका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उप वन मंडला अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश सोमवार को जारी किए। उक्त आदेश वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जे.पी. पाठक के हस्ताक्षर से जारी हुआ। जारी किए गए आदेश के अनुसार कुनाल मिश्रा (2024) प्रशिक्षु भा.व. से. अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग., नवा रायपुर अटल नगर से उप वनमण्डलाधिकारी, अम्बिकापुर वनमंडल, सरगुजा, सुश्री मृगजा जालिंदर यादव (2024) प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग., नवा रायपुर अटल नगर से उप वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा, वनमण्डल कटघोरा, परख सारडा (2024) प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग., नवा रायपुर अटल नगर से उप वनमण्डलाधिकारी, सुकमा, वनमण्डल सुकमा, सुश्री प्रीति यादव (2024) प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग., नवा रायपुर अटल नगर से उप वनमण्डलाधिकारी, उत्तर नारायणपुर, वनमण्डल नारायणपुर तथा सुश्री यशस्वी मौर्या, (2024) प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग., नवा रायपुर अटल नगर से राजनांदगांव, वनमण्डल उप वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव में नवीन पदस्थापना की गई है।

सुरता चंद्रशेखर के... विचार संवाद कार्यक्रम 6 अगस्त को

रायपुर। चंद्रशेखर जन्मशती समारोह आयोजन समिति छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा विचार संवाद कार्यक्रम -सुरता चंद्रशेखर के-गुरुवार 6 अगस्त को विमतारा ,मधु पिल्लै चौक,विद्युत नियामक आयोग कार्यालय के पास,शांतिनगर में दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक रखा गया है। समिति की ओर से जानकारी देते हुए मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में श्री रमाशंकर सिंह, पूर्व मंत्री मध्यप्रदेश, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव,राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर जन्मशती समारोह आयोजन समिति,श्री प्रदीप चौबे,पूर्व विधायक एवं समाजवादी चिंतक दुर्ग,श्री आनंद मिश्रा,समाजवादी चिंतक बिलासपुर प्रमुख वक्ता होंगे।

साहू समाज का आई.टी. सेल की नई कार्यकारिणी घोषित

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ (पंजीयन क्रमांक 33/61) की एकीकृत नियमावली द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू की अनुशंसा पर प्रदेश आई.टी. सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू ने संगठन की कार्यक्षमता, डिजिटल सशक्तीकरण एवं समाजहित के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी विस्तार की द्वितीय सूची जारी की है। जारी सूची में प्रदेशभर के सभी संभागों को संतुलित एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए कुल 114 पदाधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें 8 प्रदेश सह संयोजक, 1 बस्तर संभागीय संयोजक, 25 संगठन सचिव, 20 संयुक्त सचिव, 11 मीडिया प्रभारी, 6 सह मीडिया प्रभारी, 36 सोशल मीडिया प्रभारी तथा 7 कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। यह विस्तार संगठन की समावेशी कार्यशैली और प्रदेशव्यापी सहभागिता का परिचायक है। प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा, अनुशासन एवं समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए समाजहित में कार्य करें तथा संगठन को नई दिशा और गति प्रदान करें।

महावीर थाली में गंदगी मिलने पर लगा 8 हजार का ई जुर्माना

रायपुर। स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन 10 कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में निगम का अमला पचपेड़ीनाका चौक के पास स्थित महावीर थाली पहुंचा जहां उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गन्दगी मिलने के साथ ही स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जाना पाया गया और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। जोन 10 जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने संचालक को भविष्य के लिए नियमानुसार कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल 8 हजार रूपये का ई जुर्माना किया।

एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक

रायपुर। उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनालॉग पनीर तथा अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने जिले के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से शासन के निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की अपील की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। विभागीय परीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण एवं जोखिम मूल्यांकन में यह सामने आया कि कुछ उत्पाद वास्तविक दूध से निर्मित नहीं होने के बावजूद उन्हें पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने धरसींवा विधानसभा को दी निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात

डीएमएफ से 19.65 लाख की लागत से उपलब्ध कराई गई आधुनिक एम्बुलेंस, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई मजबूती

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा विधायक श्री अनुज शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एम्बुलेंस के चालक को चाबी सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसी सोच के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी मरीज के लिए उपचार के शुरुआती क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर अस्पताल पहुंचने से अनेक गंभीर परिस्थितियों में जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों, बुजुर्गों तथा सड़क दुर्घटनाओं या अन्य आकस्मिक घटनाओं में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा न केवल चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाएगी, बल्कि क्षेत्रवासियों में स्वास्थ्य सुरक्षा का विश्वास भी मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अस्पतालों के उन्नयन, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, दवाइयों की सुगम उपलब्धता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। उनका कहना था कि स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध समाज और विकसित राज्य की आधारशिला होते हैं, इसलिए जनस्वास्थ्य से जुड़े प्रत्येक प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

इस अवसर पर धरसींवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से एक आधुनिक एम्बुलेंस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के माध्यम से लगभग 19 लाख 65 हजार रुपये की लागत से यह अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से धरसींवा क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज़ और प्रभावी ढंग से मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि यह एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धरसींवा को सौंपी गई है, जहां से इसका संचालन किया जाएगा। यह सेवा चौबीसों घंटे क्षेत्रवासियों को उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को रेफरल अस्पतालों तक सुरक्षित एवं समयबद्ध पहुंचाने में भी यह एम्बुलेंस अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएमएफ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई यह निःशुल्क एम्बुलेंस क्षेत्र के हजारों नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

बैज को लाशों पर राजनीति करते हुए शर्म से गड़ जाना चाहिए : शताब्दी पाण्डे

■ **भूपेश सरकार में बस्तर में शहीद जवानों के शव गृह ग्राम नहीं पहुँचा पाए थे, आज बैज किस मुँह से भाजपा सरकार पर उंगली उठा रहे हैं?**

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डे ने तीखा हमला बोला। श्रीमती पाण्डे ने कहा कि जिस कांग्रेस की भूपेश सरकार नक्सली हमले में शहीद जवानों का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में नहीं करवा पाई, उस कांग्रेस के प्रदेश मुखिया बैज को अब लाशों पर राजनीति करते हुए शर्म से गड़ जाना चाहिए।

श्रीमती पाण्डे ने कहा कि कुलगाम आतंकी हमले में मृत छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों के शवों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों के चलते छत्तीसगढ़ नहीं ला पाने को लेकर रूदाली रूदन कर रहे बैज को अपनी पूर्ववर्ती सरकार का काला इतिहास याद रखना चाहिए। बैज को यह नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलियों की गीदड़ भभकी के आगे मिमियाते हुए घुटनों पर आई कांग्रेस की पिछली भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के शवों को बस्तर सम्भाग में ही उनके गृह ग्राम तक पहुँचाने में नाकाम रही थी। इससे अधिक शर्मनाक और कायराना राजनीतिक चरित्र किसी प्रदेश सरकार का और क्या हो सकता है? आज प्रदेश सरकार पर संवेदनहीनता की तोहमत लगा रहे बैज की संवेदनशीलता तब वेंटीलेटर पर क्यों थी?

श्रीमती पाण्डे ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार जवानों के बलिदान और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी, उसके नेता आज किस मुँह से भाजपा की संवेदनशील सरकार पर उंगली उठा रहे हैं? बैज आज प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करने से पहले अपनी पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की इस कायराना करतूत को क्यों भूल गए? श्रीमती पाण्डे ने कहा कि भाजपा सरकार सदैव प्रदेश के नागरिकों, मजदूरों और जवानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। कांग्रेस केवल संवेदनशील मुद्दों पर घिनौनी और निचले स्तर की राजनीति करना जानती है, लेकिन प्रदेश की जनता उनके इस दोहरे रवैये और छलावे को भली-भाँति पहचानती है।

प्रदेश स्तरीय भव्य कलश वन्दन अभियान कार्यक्रम आज, मुख्यमंत्री साय रहेंगे उपस्थित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के निमित्त आयोजित प्रदेशस्तरीय भव्य कलश वन्दन अभियान के तहत वाराणसी से पवित्र माटी व जलयुक्त कलश के वितरण का कार्यक्रम कल 4 अगस्त को रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित पं. दीनदयाल ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय के साथ ही प्रदेश के साधु-संत एवं विभिन्न समाजों के समाज प्रमुख उपस्थित रहेंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संत रविदास जयंती कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अखिलेश सोनी ने बताया कि संत रविदास के समरस समाज के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ये पवित्र कलश में प्रदेश के सभी जिलों में पहुँचेंगे। संत रविदास की 650वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी व जल का स्वागत अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में निरंतर चलाया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश में समरसता और सद्भाव का वातावरण निर्मित हो सके। श्री सोनी ने बताया कि भाजपा द्वारा भव्य कलश वन्दन अभियान के लिए 36 रथ बनाए गए हैं जो प्रदेशस्तरीय भव्य कलश वन्दन अभियान कार्यक्रम के पश्चात भाजपा के सभी संगठनात्मक जिलों में पहुँचेंगे। अगले चरण में जिलास्तरीय कलश वन्दन कार्यक्रम होगा जिसमें जिलों की मण्डल इकाइयों को ये कलश वितरित किए जाएंगे जो मण्डल के प्रमुख गाँवों में जाएंगे और विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात मंदिरों में ये कलश रखे जाएंगे।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 गांवों का होगा चयन

■ **प्रत्येक ग्रामसभा को मिलेगी 15 लाख की स्वीकृति**

■ **आदिम जाति विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी**

रायपुर। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 ग्रामों का चयन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इन ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (सीएफआरएमपी) तैयार कर लागू की जाएगी। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

आदिम जाति विभाग द्वारा कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्रामसभा में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्रामसभा के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए ग्रामसभा के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल करंट अकाउंट भी खोला गया है।

पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार ने जिलों से ऐसे 160 गांवों का चयन क्लस्टर आधारित और परस्पर जुड़े क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

पत्र में कहा गया है कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार तकनीकी सहयोगी, सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय संस्थाओं की सेवाएं भी ले सकेगी। इन संस्थाओं की सेवाएं ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं विधिवत अनुमोदन के बाद लिया जा सकेगा। ये संस्थाएं ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी में सहयोग देंगी।

आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि इस पहल से वन अधिकार अधिनियम-2006 का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन होगा, ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत होगी तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी।

रेलवे में 2430 रूट किमी पर तेजी से हो रहा है कवच का विस्तार

■ **कवच से संरक्षित हो रही भारतीय रेल की रफ्तार**

बिलासपुर/रायपुर। भारतीय रेल आधुनिक तकनीक के माध्यम से रेल संरक्षा को नए आयाम प्रदान कर रही है। यात्रियों संरक्षित, विश्वसनीय एवं निर्बाध रेल यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली कवच का चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है। यह प्रणाली ट्रेन संचालन के दौरान संभावित मानवीय त्रुटियों को न्यूनतम करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रेल संरक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग का ही परिणाम है कि भारतीय रेल में परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 तथा वर्ष 2025-26 में केवल 16 रह गई है। संरक्षा अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा संरक्षा मद में लगातार निवेश भी बढ़ाया जा रहा है।

कवच भारतीय रेल के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा

विकसित विश्वस्तरीय सील-4 प्रमाणित स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। यह प्रणाली लोको पायलट को वास्तविक समय में सिग्नल, गति सीमा, लक्ष्य दूरी तथा मूवमेंट अथॉरिटी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती है। यदि किसी कारणवश लोको पायलट निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करता अथवा खतरे वाले सिग्नल को पार करने की स्थिति बनती है, तो कवच स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को संरक्षित रोक देता है। घने कोहरे जैसी परिस्थितियों में भी यह प्रणाली संरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है।

कवच प्रणाली ट्रैक पर स्थापित आरएफआईडी टैग, यूएचएफ रेडियो संचार, स्टेशन इंटरलॉकिंग एवं ऑनबोर्ड उपकरणों के माध्यम से ट्रेन की स्थिति, गति एवं मार्ग की सतत निगरानी करती है। यह संरक्षित दूरी का निरंतर आकलन करते हुए आवश्यकता पडऩे पर स्वतः ब्रेक लगाती है तथा संभावित दुर्घटनाओं को टालती है।

कृषि मंत्री नेताम ने श्री सत्य साई ग्राम का किया दौरा

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम रविवार को श्री सत्य साई ग्राम, मुद्देनहल्ली, चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक) का दौरा किया। मंत्री श्री नेताम ने अपने प्रवास के दौरान सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी, जो वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के संस्थापक एवं वैश्विक मानवतावादी हैं, से भेंट की। सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी 100 से अधिक देशों में पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निस्स्वार्थ सेवा और आध्यात्मिकता पर आधारित वैश्विक जनकल्याण अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए संचालित मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम को और अधिक सशक्त बनाने हेतु सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि कोई भी बच्चा खाली पेट विद्यालय न जाए, तथा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने अत्याधुनिक साईश्योर एलएलपी न्यूट्रास्यूटिकल संयंत्र का भी अवलोकन किया, जहाँ वैज्ञानिक रूप से विकसित साईश्योर पोषण अनुपूरक का निर्माण किया जाता है। यह पोषण अनुपूरक श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, जो वर्तमान में देशभर के 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक शासकीय विद्यालयों के बच्चों तक पहुँच रहा है।

मंत्री श्री नेताम ने श्री सत्य साई ग्राम स्थित समेकित शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिसरों, जिनमें शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शामिल हैं, का भी भ्रमण किया।

उन्होंने सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी के दूरदर्शी नेतृत्व में संचालित इस समग्र सेवा मॉडल की सराहना की तथा पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में मिशन द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए लाखों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की सराहना की। यह दौरा छत्तीसगढ़ शासन एवं वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के मध्य बच्चों के पोषण एवं समग्र विकास से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

सावन के पहले ही दिन महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लगी लंबी लाइन

रायपुर। तीन अगस्त को सावन का पहला सोमवार था लेकिन शहर और आसपास के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, आरोग्य और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे थे। रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ मंदिर में विशेष पूजा रात 2 बजे से ही शुरू हुई और यहां शिवलिंग का गणेश के रूप में श्रृंगार किया गया था। वहीं बूढ़ा तालाब स्थित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पट सुबह 3:30 बजे खोले गए और सुबह 6 बजे महाआरती हुई। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह-जगह भंडारा लगाया गया है जहां लोगों ने कांवडियों को भोजन, फल और पेयजल मुहैया कराया गया। सावन के पहले सोमवार पर प्रदेशभर के शिवालयों में दिनभर पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा है।

राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना रात 2 बजे से ही शुरू हो गई। यहां शिवलिंग का गणेश स्वरूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह 4 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मान्यता है कि यहां नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने पर भगवान शिव उसे अवश्य सुनते और पूरी करते हैं। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं ने कराया था। हटकेश्वरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही जल चढ़ाने के लिए पहुंच गए और पट खुलने से पहले तक लंबी कतारे लग चुकी थी जहां श्रद्धालुओं ने मंदिर समिति के द्वारा की गई व्यवस्था के तहत महादेव को जल चढ़ाया। वहीं दूसरी ओर पहले ही दिन कवाडियों की टोली भी पहुंची

और वे भी लाइन में लग कर शिवजी को जल अर्पित किया और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नदी महाराज के समक्ष अपनी बातें रखी। वहीं दूसरी ओर बूढ़ा तालाब स्थित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पट सुबह 3:30 बजे खोले गए। सुबह 6 बजे महाआरती हुई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

गरियाबंद के भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना किया। वहीं मंदिर परिसर में कांवडियों का तांता लगा रहा और श्रद्धालुओं और कांवडियों की सेवा के लिए जगह-जगह भंडारा लगाया गया है जहां कांवडियों को फल और पेयजल मुहैया कराया गया।

सरगुजा के ऐतिहासिक देवगढ़ में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जहां अर्धनारीश्वर शिव की पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं 10वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महेशपुर शिव मंदिर में भी सुबह से जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे।

मनेन्द्रगढ़ में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हसदेव नदी से कांवड़ में जल भरकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ मंदिरों में पूजा-अर्चना की। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की थीं। रायगढ़ में सावन के पहले सोमवार को महादेव मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, कोसमनारा स्थिति बाबाधाम सहित शहर व ग्रामीण अंचल के शिव मंदिरों में श्रद्धालु ने शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। वहीं सावन के पहले सोमवार को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी थी और वे माता रानी से सुख-समृद्धि की कामना करते हुए पूजा-अर्चना किया।

आंदोलन के नाम पर हद की बेशर्मी!

विनीत नारायण

नीट पेपर लीक पर 'जेन-की' का जंतर-मंतर पर हुआ धरना पिछले हफ्तों में पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा में रहा। धरने का उद्देश्य गलत नहीं था। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस की जो दमनकारी लाठियां चलीं उसकी कतई जरूरत नहीं थी। बावजूद इसके इस आंदोलन को जो कुछ सफलता मिली, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पर इस आंदोलन की जिस बात ने मुझे बहुत विचलित किया, वह है भाषा की अभद्रता। जिसने शालीनता की सारी हदें पार कर दीं। अगर मुझ पर ड्क्षलगभेद का आरोप न लगे तो मैं यह खुल कर कहना चाहूंगा कि जिस तरह की गंदी गालियां, अश्लील भंगिमाएं और नारेबाजी आंदोलन में शामिल कुछ लड़कियों ने कीं, वे एक सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं की जा सकतीं। लड़कियों का मैं खासतौर पर इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अब तक भारतीय समाज में लड़कियों को कभी ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया था। लड़के तो प्रायः गाली-गलौज की भाषा में बात करते ही हैं, पर सब लड़के ऐसे नहीं होते। ज्यादातर मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मैं पिछले 50 वर्षों से हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं, इसलिए अक्सर मेरे मुंह से 'साला' गाली निकल जाती है। मेरे बेटे जो अब 40 वर्ष के आस-पास हैं, बचपन से ही मुझे इस पर टोकते आए हैं, ''आप कैसी भाषा बोलते हैं?'' इसलिए मैं यह सावधानी बरतता हूं कि अपने परिवार के सामने 'साला' जैसी गाली का भी इस्तेमाल न करूं। जंतर-मंतर के प्रदर्शन में कुछ छात्रों ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वह सोशल मीडिया के माध्यम से घर-घर और गांव-गांव तक पहुंची। जरा सोचिए कि शालीनता के दायरे में रहने वाले करोड़ों युवक-युवतियों पर इसका क्या असर पड़ा होगा? अभिजात्य वर्ग के या पढ़े-लिखे समाज के युवाओं के इस निकृष्ट व्यवहार को देख कर हो सकता है कि गांवों में रहने वाले लड़के-लड़कियां भी आधुनिक दिखने की ललक में इस तरह की अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करने लगें। दूसरी तरफ दिल्ली की झुग्गियों में पला-बढ़ा एक निर्धन नौजवान मोहम्मद इरफान इसी आंदोलन में रातों-रात पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बन कर सामने आया। गरीब परिवार में पैदा हुए इरफान के पास औपचारिक शिक्षा की डिग्रियां नहीं हैं, पर जिस संयत भाषा में उसने इस आंदोलन के मुद्दों को मीडिया के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया, वह काबिले तारीफ है। संविधान से लेकर, देश के राजनीतिक इतिहास, सामाजिक आर्थिक बदहाली और सनातन धर्म की गहराइयों तक जिस ज्ञान का प्रदर्शन उसने किया, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। इरफान का व्यक्तित्व इस आंदोलन के उन उद्दंड और संस्कारहीन युवाओं के गाल पर सीधा तमाचा है। इसी क्रम में यहां मैं एक और चिंतनीय प्रवृत्ति की ओर इशारा करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों से महानगरों में 'स्टैंड-अप कॉमेडी' का एक नया चलन शुरू हुआ है। लोकतंत्र में समाज और सरकार पर कटाक्ष करने के अनेक माध्यम होते हैं। प्राचीन काल से यह कार्य विदूषक करते आए हैं। तनाव भरे जीवन में हंसना-हंसाना सबको राहत देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कॉर्पोरेट जगत में कम उम्र में ही बुलंदियों को छूने वाले युवा, आज सबसे ज्यादा तनाव ग्रस्त हैं। इसलिए बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम जैसे शहरों में अचानक 'स्टैंड-अप' कॉमेडियनों की बाढ़ आ गई है। इनमें अधिकतर कॉमेडियन ऐसे हैं जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, सामाजिक-राजनीतिक समझ और अपने इर्द-गिर्द की दुनिया पर पैनी नजर रख कर जो कुछ प्रस्तुत करते हैं, वह न सिर्फ श्रोताओं को हंसी से लोटपोट कर देता है, बल्कि सरकार और समाज की कमजोरियों को सहज ही उजागर कर देता है।

जेन-जी ने उजागर की खामी क्या लाभ ले पाएगा विपक्ष?

शेखर गुप्ता

आप अपने राजनीतिक रुझान के अनुसार जंतर मंतर को एक क्रांति के रूप में अथवा एक गुजरे हुए तूफान के रूप में देख सकते हैं। मेरे तर्कों से किसी की सोच नहीं बदलने वाली। बहरहाल, क्या मैं यह कहने का प्रयास करूं कि क्या हुआ और क्या नहीं? जो कुछ हुआ वह मोदी सरकार के प्रति पहला सार्वजनिक और खुल्लम-खुल्ला विरोध और उपहास है। अगर उन्होंने 20 जुलाई की हिंसा के बाद इतनी तत्परता से प्रतिक्रिया दी तो उसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें एहसास हुआ कि विरोध कर रहे युवाओं (या अधिकतर बच्चों) में से 95 फीसदी से भी अधिक मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के हिंदू हैं।

यह उनका बुनियादी वोट आधार है। आप इसे जेनज़ी का लेबल देकर तुच्छ बना सकते हैं और पूरी चर्चा खासतौर पर टीवी पर होने वाली चर्चा को उनकी भाषा, उनके द्वारा दी गई गालियों पर मोड़ सकते हैं। लेकिन यह जेनज़ी कितना अलग तरह से सोचती है इस पर कोई भी चर्चा उनके द्वारा दिखाई गई अवज्ञा को तुच्छ नहीं बना सकेगी।

पहली बात तो यह कि ये अवज्ञा उस शारीरिक जोखिम के बावजूद थी जो 20 जुलाई को हुई पिटाई के बाद भी उनके जंतर मंतर लौटने के संकल्प से स्पष्ट है। दूसरी बात उनमें भविष्य के करियर को लेकर कोई भय नहीं नजर आया या कहें तो एक हद तक लापरवाही नजर आई। यह देश की राजधानी में हुआ अब तक का सबसे उग्र छात्र आंदोलन था। इससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में मंडल विरोधी आंदोलन हुआ था। उसमें उस दौर के युवाओं ने विरोध किया था। कुछ ने तो आत्मदाह का प्रयास भी किया था। इससे उस समय राजीव गोस्वामी और सुरिंदर सिंह चौहान की मृत्यु हुई थी।

दोनों ही मामलों में प्रेरणा एक जैसी थी- करियर से जुड़ी संभावनाएं, नौकरियां और शिक्षा। इनमें पहला आंदोलन स्पष्ट रूप से ऊंची जाति के लोगों का था जबकि इस बार अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले, मीम बनाने वाले उच्च मध्य वर्ग के युवा हैं। चार दशक के अंतराल पर आंदोलनरत हुई दो पीढ़ी लेकिन पुलिस या दमन का कोई भय नजर नहीं आया।

इन युवाओं ने अभिजात वर्ग के बीच खुद अपना लिए गए मौन को तोड़ दिया। यह वर्ग मोदी की आलोचना में एक भी शब्द नहीं बोल

रहा था। बहुत हुआ तो दाएं-बाएं देखकर थोड़ा फुसफुसा लिया जाता था। अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक बड़ा जनसमूह ऐसा है जो विकसित भारत या अमृतकाल जैसे नारों से अप्रभावित है।

आज के जेनज़ी का बड़ा हिस्सा 2047 तक 50 वर्ष की आयु का होगा और सबसे छोटी आयु वाले 35 वर्ष के होंगे। उनकी जिंदगियां तब तक निकल चुकी होंगी। इतना लंबा इंतजार करने का धीरज किसके पास है? निश्चित रूप से इस पीढ़ी के भारतीय युवाओं के पास नहीं और कहीं के भी युवाओं के पास नहीं। इसके विपरीत यह 50 वर्ष से अधिक आयु वाला मध्यम या उच्च-मध्यम वर्ग में भाजपा के मतदाता के साथ यह तरीका काम कर सकता है। लक्ष्य बहुत दूर भविष्य का रखा गया है जहां बुजुर्ग उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए मोदी सरकार सुरक्षित है। बच्चे इतनी दूर देख नहीं सकते।

मोदी की आलोचना करने वाले कई लोग इसे श्रीलंका, बांग्लादेश या काठमांडू में हुए युवाओं के आंदोलन से जोड़कर देख रहे थे। ऐसा सोचना भारतीय लोकतंत्र, हमारी मजबूत व्यवस्था दोनों का अपमान है। साथ ही यह एक भ्रम को भी दर्शाता है जिसके तहत यह सोचा जा सका कि एक निर्वाचित सरकार को इस कदर आसानी से हटाया जा सकता है। युवाओं ने मोदी विरोधियों के लिए दरवाजा जरूर थोड़ा सा खोल दिया है। उन्होंने मोदी सरकार की कमी उजागर कर दी है। वह यह कि मोदी सरकार के मन में अपने सबसे वफादार जनाधार के बीच अपनी लोकप्रियता को लेकर जो धारणा है वह हकीकत से काफी दूर है। उस जनाधार में सरकार से निराश लोगों की तादाद बढ़ रही है।

इस पर मुझे 2018 में छत्तीसगढ़ चुनावों के दौरान वहां के एक गांव में हुई बातचीत याद आती है जहां मेरे साथ प्रणय रॉय के अलावा दोराब सोपरीवाला भी थे। हमने एक ग्रामीण से पूछा था कि जब रमन सिंह की भाजपा सरकार उन्हें उतना कुछ दे ही रही है तो वे बदलाव क्यों चाहते हैं? इस पर उस ग्रामीण ने जवाब दिया, 'अब काफी समय हो गया उन्हें। क्या आप रोज-रोज एक ही सब्जी खाते हुए बोर नहीं हो जाते। भले ही वह आपकी पसंदीदा सब्जी हो!' सबक यह है कि थकान और ऊब कुछ पुराने वफादार मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकती है।

यही बात इन प्रदर्शनों ने रेखांकित की। भाजपा ने इसे समझा, तभी उन्होंने अपने दो सबसे महत्त्वपूर्ण चेहरों को भेजा। स्वास्थ्य मंत्री और छह साल तक पार्टी अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह,जो अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी संवेदनशील मंत्रालयों के प्रभारी हैं। यही कारण था कि उनका निर्देश था कि प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी बरती जाए, उनकी सभी मांगें मान ली जाएं और यहां तक कि साझा संवाददाता सम्मेलन भी किया जाए।

भूमि अधिग्रहण और कृषि कानूनों पर मोदी सरकार ने पहले लचीलापन दिखाया था। अब हमने कमजोरी देखी। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रदर्शन करने वाले उनके मतदाता आधार से थे। और यह भी तथ्य है कि उनका आधार इससे कहीं व्यापक है।

यह बात हमें इस बिंदु पर लाती है कि यह प्रदर्शन आखिर क्या नहीं था? पहली बात, कोई क्रांति नहीं हुई और आप फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के गीत को विराम दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में उत्तर भारत कांवड़ यात्राओं से पट जाएगा। जोर-जोर से डीजे बजेंगे और श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए भंडारों में भोजन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर कांवड़ ले जाने वालों पर फूल बरसाएंगे। इनमें भी अधिकांश जेनज़ी होंगे। लब्बोलुआब यह कि भाजपा के वफादार युवाओं की भी कमी नहीं।

आगे की राजनीति में जेनज़ी द्वारा दिखाई गई कमी का लाभ लेने की कोशिश होगी। भाजपा अपनी समस्या को समझ चुकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं। लेकिन इससे मतदाताओं की ऊब कैसे दूर होगी? क्या वह अपनी सरकार को फिर से सशक्त कर पाएंगे? मंत्रिमंडल में वही पुराने चेहरे हैं। युवाओं को सीधे प्रभावित करने वाले मंत्रालयों की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय में अब पांचवे मंत्री के पास प्रभार है और जल्द ही छठा होगा। कौशल विकास में चार मंत्री आ चुके हैं और अगर यह परियोजना सफल होती तो बेरोजगारी या अधूरा रोजगार कम होता। और वे चार मंत्री कौन रहे? राजीव प्रताप रूडी, धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्र नाथ पांडे, फिर प्रधान और अब राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ।

हरियाणा के राव इंद्रजित सिंह 2004 से एक बार (2009-14) के अंतराल को छोड़कर लगातार राज्य मंत्री रहे हैं। अब उनके पास सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना है। मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया लेकिन मंत्रालय अब भी मौजूद है। जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी क्रमशः एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और भारी उद्योग संभालते हैं। दोनों ही रोजगार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

विपक्ष इन मौकों का लाभ लेना चाहता है। बस यह याद रखे कि सत्ता ऊपर से नहीं आती। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत में कोई शक्तिशाली नेता किसी चुनौतीकर्ता से पराजित नहीं होता। वे खुद को हराते हैं। इंदिरा गांधी ने आपातकाल से ऐसा किया, राजीव गांधी ने शाह बानो से अयोध्या तक कई गलतियों से, वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग के नशे में समय से पहले चुनाव कराकर। 2014 में नरेंद्र मोदी एक चुनौतीकर्ता के रूप में उभरे। तब तक मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन चार साल से पंगु बनी हुई थी।

हर शक्तिशाली नेता को पराजित करने के लिए विपक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिली जिसने जन आंदोलन खड़ा किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ और वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ ऐसा किया। इन तीन उलटफेरों यानी इंदिरा, राजीव और संप्रग के मामलों में आरएसएस गहराई से शामिल था। कांग्रेस के पास ऐसी कोई वफादार जमीनी फौज नहीं है और यह उनके लिए एक बड़ी बाधा है। अब उनके पास इस नए अवसर पर काम करने के लिए तीन साल हैं। मोदी-शाह भाजपा के पास खुद को बदलने और पुनर्निर्माण करने के लिए भी यही समय है।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसी तरह मेरु को काञ्चनगिरि कहने का अभिप्राय भी उक्त पर्वत में अधिक मात्रा में सुवर्ण का होना हो सकता है। इस प्रकार इक्षुरसोद सुरोद आदि आदि नामों को लाक्षणिक मानने पर असम्भवता का सन्देह अवशिष्ट न रहेगा।

जैसे वर्तमान समय में उत्तरीय ध्रुव के निकटवर्ती एक द्वीप का नाम ग्रीनलण्ड प्रसिद्ध है, जिसका अक्षरार्थ हरा स्थान होता है, परन्तु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि इस द्वीप की [मिट्टी, पत्थर, दूध और पानी आदि] सभी चीजें हरे रङ्ग में सनी हुई हों, किन्तु उपजाऊपन के कारण हरे भरे शाद्वलों के आधिक्य से ही इसका ऐसा नाम पड़ गया है।

इसी तरह अमृतसर (पंजाब) में सिक्ख सम्प्रदाय के प्रसिद्ध हरिमन्दिर का नाम् गोल्डन टैम्पल मशहूर है जिसका अर्थ सोने का मन्दिर होता है, परन्तु एतावता यह नहीं समझना चाहिए कि उसमें ईंट चूना पत्थर आदि लगा ही नहीं है किन्तु शिखर के ऊपर सुनहरी झोल होने के कारण ही ऐसा नाम पड़ गया है।

ठीक इसी प्रकार क्षीरोद, दधिमण्डोद और सुरोद आदि समुद्र नामों की तथा कांचनगिरि %सुमेरु% की व्यवस्था समझनी चाहिए।

परिमाण ठीक हैं

परिमाण-वैपरीत्य का तीसरा आक्षेप भी उसी दशा में उत्पन्न होता है जब कि हम इस लघु कलेवर भूपिण्डमात्र को भूमण्डल समझ बैठते हैं। परन्तु जब पौराणिक परिभाषा के अनुसार भूमण्डल का आयाम सूर्य्यताप और चन्द्र-संस्थान तक विस्तृत समझ लिया जाता है तो परिमाण वैपरीत्य का सन्देह अपने श्राप समाहित हो जाता है, जैसे भमण्डल के परिमाण को ही लीजिये -

क्रमशः ...

आधा पैसा मिलने पर आधा काम करते थे किशोर कुमार

अनन्या मिश्रा

हिंदी सिनेमा के गायक किशोर कुमार का 04 अगस्त को जन्म हुआ था। वह संगीत के उस्ताद होने के साथ ही अपनी शानदार गायन प्रतिभा के लिए भी जाने जाते थे। किशोर कुमार गायक होने के साथ ही अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक और पटकथा लेखक भी थे। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गाने आज भी लोग गुनगुना या सुनना पसंद करते हैं। भारतीय संगीत इंडस्ट्री में किशोर कुमार का योगदान अतुलनीय है।

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 04 अगस्त 1929 में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। इनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार अभिनेता अशोक कुमार के भाई थे। किशोर कुमार अपनी गायन प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कई गायन प्रशिक्षण नहीं लिया था।

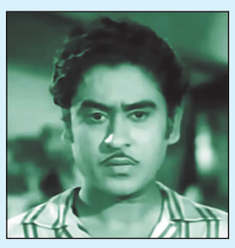

किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते समय अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया। हिंदी सिनेमा में किशोर कुमार की पहचान एक गायक और अभिनेता के तौर पर हुई। उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग, स्वभाव और स्वर में अनूठेपन से सबको चौंका दिया था। धीरे-धीरे वह हिंदी सिनेमा के फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक बन गए।

किशोर कुमार की संगीत प्रतिभा ने हिंदी सिनेमा को कई सुरों से भरा था। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई हिट गाने दिए थे। सिंगर ने पन्ना की तमन्ना है, बाबुल का घर, दिल क्या करें, नीले नीले अंबर पर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, गाता रहे मेरा दिल, मेरे सामने वाली खिड़की में और कयामत होगी, जैसे सदाबहार गाने गाए हैं। उस समय किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज हुआ करते थे। किशोर कुमार ने हिन्दी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फ़िल्मों के लिए भी लगभग 700 गीत गाए। किशोर कुमार को आठ फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार मिले, उनको पहला फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार 1969 में अराधना फ़िल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए दिया गया था। किशोर कुमार की विशेषता यह थी कि उन्होंने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हों। सिंगर किशोर कुमार ने 4 शादियां की थीं। जिसमें पहली शादी सला 195 में गायिका रूमा गुहा ठाकुरता से की थी। लेकिन साल 1958 में यह रिश्ता खत्म हो गया था। इसके बाद किशोर कुमार ने दूसरी शादी साल 1960 में मधुबाला से की थी। लेकिन साल 1969 में मधुबाला की मौत हो गई। उन्होंने तीसरी शादी साल 1976 में योगिता बाली से की। लेकिन दो साल बाद 1978 में रिश्ता भी खत्म हो गया। जिसके बाद किशोर कुमार ने चौथी शादी साल 1980 में लीना चंद्रावरकर से की थी, जोकि आखिरी समय तक उनके साथ रहीं। वही 13 अक्तूबर 1987 को 58 साल की उम्र में किशोर कुमार ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।

स्पेन में जबरन क्यों घुसे हजारों मुस्लिम?

अभिनय आकाश

गरीबी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तब सीमाओं के मानचित्र धुंधले पड़ जाते हैं। और जब कोई देश मानव आबादी को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे तो मंजर वही होता है जो इस वक्त स्पेन के अफ्रीकी एनक्लेव सोटा में नजर आ रहा है। भूमध्य सागर का वो मुहाना जो अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का सेतु होना चाहिए था। पिछले 24 घंटों में एक अंतहीन मानवीय और सुरक्षा संकट का गवाह बन चुका है। नागरिक तैर कर बाढ़ फांदकर चट्टानों को पार कर स्पेनिश सरजमी पर दाखिल हो चुके हैं। कम से कम 34 जिंदगियां समुद्र के खारे पानी में खामोश हो गई। सड़कें इस वक्त सहमी हुई है। दुकानें बंद हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांजेस को इसे देश की प्रादेशिक अखंडता पर हमला करार देकर सेना उतारनी पड़ी। लेकिन सवाल सिर्फ हजारों प्रवासियों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि मोरक्को की सीमा से अचानक इतनी बड़ी इंसानी लहर स्पेन में उमड़ पड़ी? क्या यह महज बेहतर जिंदगी की तलाश है या फिर यूरोप की दहलीज पर खेला जा रहा एक बड़ा जिओपॉलिटिकल गेम। आंकड़ों को ध्यान से देखिए। सोटा की कुल आबादी है 83,000 के आसपास और सिर्फ एक दिन के भीतर वहां 60,000 लोग घुस आते हैं। यानी शहर की कुल आबादी का 70त्न। समुद्र के रास्त मीलों दूर तक तैर कर आते युवा चट्टानों के सहारे आगे बढ़ते बच्चे और महिलाएं और फिर थिएटर के बाजारों में पसरती दहशत। वहां के लोकल्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उग्र और अनकंट्रोल्ड मंजर पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों से लेकर आम नागरिकों तक में डर का माहौल है। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था कि समुद्र में रोके गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत मुरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। और इसी फैसले की आड़ में आपराधिक नेटवर्क और

अफवाहों ने ऐसा तहलका मचाया कि हजारों लोग एक साथ सीमा पर टूट पड़े।

मोरक्को के तटीय शहर फनीदेक से स्पेन की जो दूरी है यह सिर्फ 3 से 5 किमी है। एक तरफ मोरक्को है जहां पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, बदहाली है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर ताकतवर यूरोपीय संघ और विकसित देश स्पेन मौजूद है। स्पेन में इस टाइम पर आपको बता दें कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हजारों लोग स्विमिंग करते हुए स्पेन के कोस्टल टाउन की तरफ पहुंच रहे हैं ताकि वह बॉर्डर्स के अंदर घुसकर सीधे यूरोपियन यूनियन में फैल सके। फेवरेबल वेदर का फायदा उठाकर यह लोग धड़ल्ले से समंदर पार कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग डूबे भी हैं। लेकिन भीड़ की रफ्तार जो है यह कम नहीं हो रही। इसमें से कई सारे लोग मोरक्को के हैं। कई अफ्रीकी युवा भी शामिल हैं। इन्हें यह सही वक्त क्यों लगता है बॉर्डर पार करने के लिए? अब आप उसे समझिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन ने हाल ही में एक रूलिंग पास की थी कि जो भी लोग समंदर के रास्ते आ रहे हैं स्पेन के अंदर आप उनको तुरंत के तुरंत वापस नहीं भेजोगे। आपको बकायदा लीगल प्रोसेस देना होगा। बस अदालत की इसी फैसले ने इन घुसपैठियों के लिए खुला दरवाजा खोल दिया। स्थाई लोग यह कह रहे हैं कि लीडर्स नेशनल इमरजेंसी लगाओ। हम इन माइग्रेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। दबाव 1000त्न बढ़ चुका है। लेकिन स्पेन की सरकार कोई स्ट्रांग एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? अब आप उसे समझिए क्योंकि वहां है कोलीजन गवर्नमेंट। सरकार

सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट और सेंटर लेफ्ट सब ने मिलकर यहां पर सरकार बना रखी है सबके अपने-अपने ओपिनियंस हैं। इसका खामियाजा भुगत रहे हैं वहां के नागरिक नेटिव्स। उधर पोलैंड जैसे देश का रवैया भी अलग है। पोलैंड साफ यह कहता है कि हम माइग्रेशन को अपने देश के खिलाफ हथियार नहीं बनने देंगे। बेलारूस बॉर्डर पर उसने इलेक्ट्रिफाइड सर्विलांस और आर्मी बिठा रखी है। कहा है कि ड्रामा यहां पर नहीं चल सकता। लेकिन स्पेन के इस कोहराम को देखकर यूरोप के जो बाकी देश हैं इनकी नींदें उड़ चुकी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है स्पेन को। मेलोनी ने यह साफ कहा है ट्वीट करते हुए कि अगर स्पेन बॉर्डर संभालने में नाकामयाब रहा तो इटली यहां पर मुख दर्शक बनकर नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो स्पेन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है एरिया की व्यवस्था को संभालने का उसे यह निलंबित भी कर सकते हैं। आखिर सेटा इतना अहम क्यों है उसे समझिए क्योंकि यह अफ्रीका और यूरोप के बीच का इकलौता लैंड बॉर्डर है। इस बार हजारों की संख्या में युवा और नाबालिक बॉर्डर के गेट को तोड़ते हुए स्पेन के अंदर घुस आए हैं। कुछ ने मोरको की तरफ से वाटर कैनन का सामना भी किया तो कुछ ने समंदर में लाशों के बीज तैर कर अपनी जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर पार। रिपोर्ट्स जो कहती है उसके मुताबिक इस रूट पर दर्जनों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी यह स्पेन में घुस रहे हैं।

स्पेन की जो जन दर दुनिया में है वो सबसे कम है और हर साल 1 लाख ज्यादा लोग जो हैं वो यहां पर रिटायर हो रहे हैं। कृषि पर्यटन और निर्माण क्षेत्रों को जिंदा रखने के लिए स्पेन को हर साल लाखों विदेशी कामगारों की जरूरत पड़ती है। यहां के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी जो सरकार है यह प्रवासियों को कानूनी दर्जा और वर्क परमिट देने की योजना पर काम कर रही है ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है यह ठप ना पड़े। एक तरफ अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए स्पेन मजबूर है तो दूसरी तरफ बेकाबू होती हुई यह भीड़ और टूटती हुई सीमाएं। सवाल यह है कि क्या यूरोप अपनी नीतियों के चक्कर में खुद अपने ही विनाश का रास्ता खोल रहा है या फिर स्पेन का यह नर्क से स्वर्ग वाला खेल यूरोप के बाकी देशों को भी तबाह कर देगा।

सेउटा संकट पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्पेन के साथ शेंगेन फ्री-ट्रैवेल (बिना वीजा यात्रा) को रोकने दी धमकी दे डाली। मेलोनी ने कहा कि सेउटा से आ रही तस्वीरें चौंकाने वाली हैं और एक बार फिर यह दिखाती हैं कि बेकाबू आप्रवासन यूरोप की सीमाओं के लिए एक ठोस खतरा है।

भारत के संदर्भ में असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य लंबे समय से अवैध घुसपैठ की समस्या से प्रभावित रहे हैं। स्पेन के इस घटनाक्रम से सीख लेते हुए भारत को इन राज्यों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल और असम की बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों, दलदल और जंगलों से घिरा है। यहाँ भौतिक रूप से कंटीली बाड़ लगाना कठिन होता है, जिससे घुसपैठियों और मानव तस्करों को घुसपैठ का आसान अवसर मिल जाता है। उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के पास स्थित है। इस क्षेत्र के आसपास अनियंत्रित घुसपैठ भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। स्पेन का संकट यह संदेश देता है कि घुसपैठ केवल एक मानवीय या क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ा विषय है। भारत को असम और बंगाल की सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन निगरानी, क्ष्स्त्र का सशक्तिकरण और अवैध दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई के जरिए सीमा तंत्र को अभेद्य बनाने की आवश्यकता है।

आज का इतिहास

1983 थॉमस संकर अपर वोल्टा के राष्ट्रपति बने।
1984 सैन्य तख्तापलट के जरिये रिपब्लिक ऑफ अपरवोल्टा में सत्ता में आने के एक साल बाद, राष्ट्रपति थॉमस सांकरा ने अपना नामो बुर्किना फासो (ध्वज चित्र) बदल दिया।
1991 ग्रीक क्रूज़ जहाज एमटीएस ओशनोस पर एक विस्फोट ने इसकी थाह को तोड़ दिया और यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर चला गया, लेकिन सभी 571 जहाज पर बच गए।
1992 जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योही कोनो ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को यौन गुलाम बनाने के लिए एक औपचारिकता जारी की।
1995 क्रोएशियाई सेना ने ऑपरेशन स्टॉर्म की शुरुआत की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से क्रोएशियाई युद्ध की स्वतंत्रता की आखिरी बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी यूरोपीय भूस्खलन।
1997 मो. ख़ातमी ने ईरान के चुनाव में जीतकर नये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।
1999 चीन ने अमेरिकी सेना के विमानों की नियमित उड़ानों को हांगकांग में उतरने की अनुमति देने से इंकार किया।
1999 बैंक न्यूज नेटवर्क ने पाया है कि एटीएम मशीनों के उपयोग में गिरावट आई है। एटीएम उपयोग के लिए सेवा शुल्क से नाराज उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है, और एटीएम लेनदेन में 2.9% की कमी होती है। दूसरी ओर, डेबिट कार्ड लेनदेन में 35% की वृद्धि हुई है।
2001 रूस व उत्तरी कोरिया ने सामरिक समझौता हस्ताक्षर किये।
2002 17 वीं राष्ट्रमंडल खेलों इंग्लैंड के मैनचेस्टर में समाप्त हुआ।
2004 नासा ने एल्टिक्स सुपर कम्प्यूटर केसी को कल्पना चावना नाम दिया।
2007 अमेरिका ने फ़ीनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया जिसका काम मंगल ग्रह की खोज करना था।
2007 तुर्की और ग्रीस के बीच एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के पूरा होने से गैस को मध्य पूर्व से यूरोप में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
2007 नासा ने फीनिक्स अंतरिक्ष यान बनाया।
2008 रिपोर्टों के अनुसार, एक अंतरराष्ट्रीय भ्रमण के 11 पर्वतारोही बर्फबारी के कारण मृत पाए गए, जिससे उनकी निश्चित रस्सियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं।
2013 अल-कायदा हमले के बारे में अर्जित ज्ञान के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 22 दूतावासों को बंद कर देता है।

आखिर क्यों पूरा नहीं कर पाते शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल

योगेंद्र योगी

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ़ इस्तीफा देने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। साल 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल %निशंक% और धर्मेंद्र प्रधान को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा।

पांचवा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, हालांकि जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोदी सरकार को तय करना है कि जोशी ही पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री रहेंगे या किसी नए चेहरे की तलाश करके उसको स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जोशी भी विवादों में रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंग रेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर जब चौतरफ़ा सवाल उठ रहे थे, तब प्रल्हाद जोशी ने इसका बचाव किया था।

सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा प्रमुख मंत्रालय रहा, जिसकी कमान पांच अलग-अलग मंत्रियों ने संभाली वहीं, गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईएनबी) ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय हैं, जिन्हें सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं।

यही कारण है कि यहां विवाद ज़्यादा हुए और अस्थिरता भी उतनी ही दिखती है। गौरतलब है कि आईएनबी में 12 साल के भीतर सात केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में पांच केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह ज़िम्मेदारी रमेश पोखरियाल निशंक को मिली। मगर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर एक महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक

जंतर-मंतर पर बैठे रहे और आख़िरकार केंद्र सरकार दबाव में आई और प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा।

नीट परीक्षा के लीक होने का मामला अलग कर दें, तो संघ से जुड़े उन सभी प्रमुख लक्ष्यों को धर्मेंद्र प्रधान बिना शोर-शराबा किए लागू करा पाने में सफल रहे हैं, जिनकी कोशिश उनके पूर्ववर्तियों ने ज़ोर लगाते हुए की और विवादों में फंसते गए। ग़ौरतलब है कि 2014 में बनी पहली मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, फिर मोदी के दूसरे कार्यकाल में वे शिक्षा मंत्री बने और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी यह ज़िम्मेदारी जारी रही। प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को बढ़ावा मिला। मातृभाषा और कई भाषाओं में शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। मगर तीन-भाषा फ़ॉर्मूला पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक वे विवाद के केंद्र में भी रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा नीति केंद्र बनाम राज्य के विवाद का मुद्दा बन गई।

मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विज़न लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये ज़रूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीक़ा अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर थीं, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासन में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गईं, वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मक़सद से लागू हुईं। संघ का मक़सद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचारधारा वाली शिक्षा-पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ मानता है कि वे मुग़लों के समर्थक रहे हैं। संघ की नज़र में, मुग़ल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। संघ पर आरोप लगते रहें कि इस एजेंडे को पूरा मोदी सरकार के जरिए कराया जा रहा है।

इसी लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार के चार शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना रहा है। स्मृति ईरानी को छोड़ दें, तो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजपेयी के ज़माने में भी संघ से आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दख़ल हमेशा चाहता रहा है। स्मृति ईरानी के साथ उनके नाम पर डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे।

स्मृति ईरानी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं थीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने में देरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्मृति से बहुत खुश नहीं था। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर-शराबा नहीं करता। यही कारण है कि फिलाहल संघ की पृष्ठभमि वाले प्रकाश जोशी को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के समय इसे लागू किया गया।

शिक्षा मंत्री रहे निशंक की पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है, जो संघ के मक़सद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि, अपने अवैज्ञानिक बयानों को लेकर भी वे विवादों में आए। उन्होंने यहां तक कहा कि चरक ऋषि ने अणु-परमाणु की खोज की थी। कोविड के समय जेईई-नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद निशंक के ख़िलाफ़ काफ़ी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए, जहां सरकार के पक्ष में फ़ैसला आया। हालांकि, तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से रह गए, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके समय भी आरोप लगे कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए केंद्र सरकार शिक्षा पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकार दिया था।

शिक्षा मंत्रालय के जरिए मोदी सरकार का सारा जोर संघ को साधने में रहा है, किन्तु शिक्षा के उत्थान के लिए बजट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बजट घटता गया और विवाद बढ़ते गए। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेज़ी से घटी है यह हिस्सा 2013-14 में कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट ही दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। चारों शिक्षा मंत्रियों के समय में लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फ़ैकल्टी के चयन में संघ की विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है।

छात्र आंदोलन : अधिकार, मर्यादा और जिम्मेदारी

किरण चोपड़ा

किसी भी लोकतंत्र में छात्रों, युवाओं को, जो देश का भविष्य हैं, अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, पेपर लीक या अन्य अनियमितताओं की शिकायत हो तो उनकी निष्पक्ष जांच और सुधार होना आवश्यक है। छात्रों की यह अपेक्षा कि उन्हें पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था मिले, स्वाभाविक और उचित है।

हाल के आंदोलन के बाद सरकार ने परीक्षा सुधारों की दिशा में कदम उठाए और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया। जो वास्तविक छात्र अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनमें से अधिकांश ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, परंतु यदि किसी आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाएं जिनका उद्देश्य केवल माहौल बिगाड़ना, गाली-गलौज करना, हिंसा करना या पुलिस पर हमला करना हो तो वह किसी भी अच्छे आंदोलन की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। हिंसा और अभद्रता का समर्थन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता।

हमें यह भी समझना चाहिए कि पुलिस भी अपना वैधानिक कर्तव्य निभाती है। यदि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो तो उसकी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अगर पुलिस अनुचित व्यवहार करे तो ?उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संवाद है, टकराव नहीं। अनुशासन है, अराजकता नहीं।

हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, मर्यादा देश-विदेश में मशहूर है। गुस्सा और निराशा किसी भी व्यक्ति को हो सकती है लेकिन हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि अपनी बात दृढ़ता से कहें परंतु मर्यादा के साथ। भारत की परंपरा संवाद, संयम और शिष्टाचार की रही है। लोकतंत्र में विचारों का विरोध

किया जा सकता है, व्यक्ति का अपमान नहीं।

समस्याओं का समाधान आंदोलन से हो सकता है लेकिन गाली-गलौज और अभद्रता से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो संदेश डालकर उनके बारे में अपशब्द कहने वालों को माफी दे दी और कहा कि ये बच्चे भटक गए हैं और इन्हें सजा की नहीं, माफी की जरूरत है। पीएम का यह बयान व्यापक उदारता से भरा है।

आंदोलन अगर ऐसा रूप लेता है तो मरीज, बुजुर्गों, बच्चों और काम पर जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है। व्यापार और रोजगार पर असर पड़ता है। समाज में तनाव और असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है। अंत में विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि आप देश का भविष्य हो। आपकी ऊर्जा, आपकी प्रतिभा और आपकी आवाज भारत के कल का निर्माण करेगी।

इसलिए आपकी बात का महत्व है लेकिन उतना ही महत्व आपकी भाषा और व्यवहार का भी है। इसके साथ मैं संसद के सदस्यों से भी यही कहूंगी कि आपको सारा देश देख और सुन रहा है। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन मर्यादा और शालीनता से। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। विरोध हो सकता है लेकिन अपमान नहीं। यही हमारे संस्कार हैं, यही लोकतंत्र की गरिमा है।

सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों पर मोदी सरकार के तर्कपूर्ण जवाब

नीरज कुमार दुबे

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ऐसी बहस छिड़ी, मानो लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से एक का भविष्य न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो। एक ओर संविधान की आत्मा और निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर सवाल उठाते न्यायाधीश थे तो दूसरी ओर संसद की सर्वोच्चता और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पक्ष मजबूती से रखती केंद्र सरकार। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला कई बार अदालत की बहस से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं पर गहन विमर्श में बदल गया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही सवाल उछाला कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त (ष्टश्वष्ट) और चुनाव आयुक्तों का पद लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उनके चयन की प्रक्रिया ऐसी क्यों न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह न रहे? अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होकर काम करे, इतना पर्याप्त नहीं है; उसे स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए।

इसी संदर्भ में अदालत ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि संसद ने 2023 का कानून बनाते समय चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने का निर्णय आखिर किस आधार पर लिया? पीठ ने याद दिलाया कि सीबीआई निदेशक और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका स्वीकार की गई है, फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के मामले में यह व्यवस्था क्यों बदली गई?

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा और पवित्रता है तथा जनता को उनके निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए। तुषार मेहता ने सवालिया अंदाज में कहा, यदि प्रधानमंत्री के फैसलों पर भरोसा ही नहीं किया जाएगा, तो क्या फिर मंत्रिमंडल के गठन के समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेना अनिवार्य कर दिया जाए? उन्होंने यह भी दलील दी कि केवल इसलिए कि कार्यपालिका के पास संख्यात्मक बहुमत है, यह मान लेना उचित नहीं कि वह संविधान विरोधी या दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीनों अंग यानि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और एक संस्था दूसरी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

लेकिन अदालत ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री पर अविश्वास जताना नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा, हम यह नहीं कह रहे कि वर्तमान समिति ने निष्पक्षता नहीं बरती है। लेकिन जैसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, उसी प्रकार चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में भी निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए।

इसी दौरान अदालत ने सरकार से एक और तीखा सवाल पूछा। पीठ ने याद दिलाया कि पहले भी अदालत ने निर्वाचित सरकार पर भरोसा जताते हुए आपराधिक

पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाने की अपेक्षा की थी। ऐसे में आज सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं? इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी तय होती है।

हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2023 के उस कानून को लेकर है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। बाद में संसद ने कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अदालत से कहा कि संसद की विधायी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। उनका कहना था कि केवल इसलिए कि कोई दूसरा मॉडल बेहतर हो सकता है, संसद द्वारा चुनी गई व्यवस्था को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसद को इस प्रकार बाधित नहीं किया जा सकता।

सरकार ने अपने हलफनामे में भी यही रुख दोहराया। केंद्र ने कहा कि यह आशंका पूरी तरह काल्पनिक है कि चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता स्वत: प्रभावित हो जाएगी। सरकार ने याद दिलाया कि सात दशक से अधिक समय तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह कार्यपालिका द्वारा होती रही, लेकिन इस दौरान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी बाधित नहीं हुए। इसलिए केवल आशंकाओं के आधार पर कानून को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह आग्रह भी किया कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं, इसलिए इसे बड़ी संविधान पीठ को भेजा जाए। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता डी. शेषाद्रि नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और संजय पारिख ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि लगभग 20 दिन तक विस्तृत सुनवाई चलने के बाद अब इस आधार पर मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग करना केवल सुनवाई को टालने का प्रयास है।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की गई है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, संसद की विधायी शक्ति और जनता के भरोसे के बीच संतुलन की नई संवैधानिक रेखा भी खींच सकता है।

नेपाल में भी मजहबी कट्टरपंथियों ने भड़काई सांप्रदायिक हिंसा?

मनोज कुमार अग्रवाल

नेपाल के दक्षिणी हिस्से मधेस और कोशी प्रांत में कांवड़ बोलबम यात्रा और मुहर्रम के लाउडस्पीकर विवाद को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत होना बिगड़ते हालात को बयान करता है यहा भी कट्टरपंथी मजहबी तत्व सिर उठाने लगे हैं। तनाव को देखते हुए सुनसरी, सिरहा, सर्लाही और जनकपुर सहित 6 से अधिक शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ़्यू लगा दिया गया है और स्थिति को काबू में करने के लिए नेपाली सेना को जमीन पर उतार दिया गया है। इस ताज़ा हिंसा के मामले चिंता बढ़ाने वाले है। नेपाल के सुनसरी जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब कई जिलों तक फैल चुकी है। तीन लोगों की मौत, कई जिलों में कर्फ़्यू और सरकार की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच जानिए आखिर नेपाल में क्या हो रहा है? हिंसा की शुरुआत और कारण लाउडस्पीकर और झंडे का विवाद- हिंसा की शुरुआत 26 जुलाई की रात सुनसरी जिले के देवानगंज (कसानगंज क्षेत्र) से हुई। वहां एक पक्ष की ओर से बोलबम यात्रा की तैयारी चल रही थी और दूसरे पक्ष का भी धार्मिक कार्यक्रम था। डीजे पर तेज संगीत बजाने और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच कहासुनी हुई, जिसने देखते ही देखते हिंसक झड़प का रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ़्यू लगाना पड़ा, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद नेपाल सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुरक्षा विशेषज्ञों, विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समय रहते राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने से हालात बेकाबू हो गए। पथराव और आगजनी- उपद्रवियों ने कई दुकानों, वाहनों और सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। हताहत और वर्तमान स्थितितीन मौतें- पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों और फायरिंग में अब तक तीन लोगों (ओम प्रकाश मेहता, जय

प्रकाश मेहता और गणेश यादव) की मौत हो चुकी है। कर्फ़्यू और सेना की तैनाती- सुनसरी और सिरहा के गोलबाजार, लहान, इनरवा और जनकपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में सेना फ्लैग मार्च कर रही है और हेलिकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। नेपाल सरकार की अपील- नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने देश के नाम संदेश जारी कर लोगों से सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत सीमा पर हाई अलर्टनेपाल के ये हिंसा प्रभावित जिले भारत के बिहार राज्य की सीमा से सटे हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत-नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) और स्थानीय पुलिस अतिरिक्त चौकसी बरत रही है तथा सीमा पार आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है।

आपको बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र में हाल के दिनों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा केवल पड़ोसी देश की कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। भारत से लगी खुली सीमा, दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक संबंध और सीमावर्ती क्षेत्रों की साझा आर्थिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह घटनाक्रम भारत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। सुनसरी जिले के कसानगंज में दो समुदायों के बीच शुरू हुआ विवाद यदि सिराहा, धनुषा और अन्य क्षेत्रों तक तनाव का कारण बन रहा है, तो इसे सामान्य स्थानीय झड़प मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हिंसा, पथराव, आगजनी और सुरक्षाबलों के साथ झड़पों के बाद नेपाल के कई संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ़्यू लगाया गया है। लोगों की आवाजाही, सभाओं, प्रदर्शनों और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाई गई है। संवेदनशील स्थानों, सरकारी कार्यालयों और प्रमुख मागों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नेपाल की सेना और सशस्त्र पुलिस बल को भी निगरानी में लगाया गया है। इन कदमों से स्पष्ट है कि नेपाली प्रशासन स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, लेकिन असली चुनौती केवल हिंसा रोकना नहीं, बल्कि उसके पीछे सक्रिय अफवाहों, उकसावे और संगठित कट्टरता की पहचान करना है। सांप्रदायिक हिंसा प्राय: अचानक दिखाई देती है, लेकिन उसकी जमीन लंबे समय में तैयार होती है। किसी धार्मिक आयोजन, जुलूस, रास्ते, नारे, सोशल मीडिया पोस्ट या मामूली विवाद को बहाना बनाकर भीड़ को भड़काया जाता है। कुछ घंटों में स्थानीय विवाद सामुदायिक संघर्ष में बदल जाता है। इसके बाद झूठी तस्वीरें, पुराने वीडियो और अपुष्ट संदेश आग में घी का काम करते हैं। नेपाल में भी प्रशासन को यह जांचना होगा कि क्या सुनसरी की घटना के पीछे कोई सुनियोजित अभियान, भड़काऊ प्रचार या बाहरी सहायता से चलने वाला नेटवर्क सक्रिय था। नेपाली मीडिया में सामने आई कथित सुरक्षा रिपोटों ने चिंता को और बढ़ाया है। बताया गया है कि नेपाल की आई पुलिस फोर्स ने कुछ वर्ष पहले ही तराई-मधेस क्षेत्र में धार्मिक और जातीय तनाव भड़काने वाले तत्वों को लेकर सरकार को सतर्क किया था। यदि वास्तव में ऐसी चेतावनी दी गई थी और उस पर समय रहते पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। खुफिया सूचनाओं का उद्देश्य केवल दस्तावेज तैयार करना नहीं, बल्कि संभावित संकट को रोकने के लिए नीति और कार्रवाई तय करना होता है। हालांकि इस संवेदनशील परिस्थिति में सबसे अधिक सावधानी भाषा और आरोपों को लेकर बरतने की आवश्यकता है। किसी पूरे समुदाय, धर्म, क्षेत्र या जनसंख्या समूह को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे तनाव और बढ़ सकता है।

जेन-जी आंदोलन का असर न्यायपालिका पर?

सनत जैन

जंतर मंतर पर हुए जेन-जी आंदोलन का असर पहले जेन-अल्फा पर देखने को मिला है। इसके बाद बाद जिस तरह से न्यायपालिका के बारे में युवा मुखर होकर अपनी बात सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं, उससे अंदेशा है कि न्यायपालिका भी निशाने पर आ गई है। कॉकरोच शब्द पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही निकला था। यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा, इसे ना तो सरकार ने सोचा था ना ही न्यायपालिका ने सोचा था, लेकिन जिस तरह से बिना किसी डर और भय के सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपनी बात कह रहे हैं। इसका असर देश के सभी वर्गों पर पढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां द्वारा न्यायपालिका में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे सवाल किए गए हैं। उसके बाद से यह मामला भी तूल पकड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट अथवा न्यायपालिका में कॉलेजियम द्वारा पहले जजों की नियुक्ति के समय जो अनुशंसा की जाती थीं, उसके कारण भी कॉलेजियम में बताए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कॉलेजियम में जो अनुशंसा की जा रही है उनमें चयन का आधार और उसके कारणों की स्पष्टता नहीं होने से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय जजों की नियुक्ति के लिए लिए जा रहे हैं उनकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट में ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ समय से सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। कई जजों की वरिष्ठता को नजर अंदाज करते हुए तथा ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से जजों को सीनियर से जूनियर बनाने और अपने इच्छित व्यक्ति को जज बनाने के लिए कॉलेजियम और सरकार के बीच में जो सांठ-गांठ हो रही है उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज भी खुलकर बोलने लगे हैं। कॉलेजियम में शामिल जजों द्वारा जो डीसेंट नोट दिया जाता था उसे भी सार्वजनिक नहीं किए जाने पर जस्टिस नागरत्ना द्वारा आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए जजों की नियुक्ति मनमाने तरीके से हो रही है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के बीच में जिस तरह की मुखरता के साथ अपनी बात कही जा रही है न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अब खुद न्यायपालिका के अंदर से आवाज उठ रही है।

न्यायपालिका का जो डर और भय था लगता है जेन-जी और जेन-अल्फा द्वारा बिना किसी डर और भय के जिस तरह से सड़कों पर आकर अपनी बात कही जा रही है उसने सभी वर्गों का डर और भय निकालने का काम किया है। देशभर में चारों ओर से निष्पक्षता की बात होने लगी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के फैसले और दो तरह के कानून को लेकर जो धारणा बनी है उसको लेकर अब देश भर में न्यायपालिका के प्रति भी आक्रोश देखने को मिलने लगा है। न्यायपालिका के प्रति पहले जो विश्वास राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच में देखने को मिलता था अब वह देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार भी बार-बार कहती है, यदि सरकार का फैसला पसंद नहीं है तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से वही फैसला आता है जो सरकार का बचाव करता है। कई राज्य सरकारों को केवल इसलिए गिरा दिया गया कि उनका फैसला समय पर नहीं हुआ। कई मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। जो मौलिक अधिकारों और संविधान से जुड़े हुए थे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी मामला पिछले 2 साल से लंबित पड़ा हुआ है। एसआईआर के मामले में भी चुनाव आयोग को न्यायपालिका का जो सर्वेक्षण मिला है, उसको लेकर तरह-तरह की धारणा न्यायपालिका के प्रति आमजनों के बीच भी बनने लगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहना की लाखों मतदाताओं के नाम यदि मतदाता सूची में नहीं है वह इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल से फैसला होने के बाद अगली बार वोट दे देंगे। अभी तक एसआईआर के माध्यम से लोकसभा चुनाव के समय जो मतदाता सूची थी उसमें से करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार नागरिकों को मिला हुआ था, उससे वह वंचित कर दिए गए। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जिस तरह की गड़बड़ी के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगे, पूर्व की चुनाव व्यवस्था को बदलते हुए मनमाने तरीके से चुनाव आयोग ने नए-नए नियम बनाए, नए-नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। इस सब की जानकारी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से छुपाई गई। इस सारी गड़बड़ी में कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता चुनाव आयोग को मिलती रही है।

राशि अनुसार चुनें पर्स का कलर

आपका पर्स और आपकी राशि

कभी तिजौरी का घर, दुकान आदि में बड़ा महत्व होता था क्योंकि वही एकमात्र धन को संग्रह करने का स्थान था। समय बीता और तिजौरी का स्थान धीरे-धीरे हटने लगा, परिणामस्वरूप आज तिजौरी बहुत कम यदा-कदा ही मिलती है। वास्तु में भी तिजौरी का वर्णन मिलता है।

पिछले कई वर्षों से पर्स का चलन बढ़ने लगा है और पर्स महिलाओं के हाथ में होना एक फैशन का रूप भी बन गया है। पुरुष वर्ग भी पर्स के बिना धन नहीं रखते। तिजौरी और पर्स में कोई विशेष अंतर नहीं रहा।

आपके पर्स का आकार, रंग आपके पर्स में रखे हुए सामान आपके जीवन में होने वाली छोटी से छोटी घटना के सूचक होते हैं। आइए जानते है इसके लाभ और हानि।

- मेष, सिंह और धनु राशि वाले अपना पर्स लाल या नारंगी रंग का रखें तो लाभ होगा।
- वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को भूरे रंग का पर्स तथा मटमैले रंग का पर्स बहुत फायदा पहुंचाएगा।
- मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले यदि नीले रंग व सफेद रंग का प्रयोग करते हैं तो मानसिक स्थिति के साथ-साथ धन के आगमन के रास्ते भी खुलेंगे।
- कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को तो हमेशा हरा रंग और सफेद रंग का प्रयोग अपने पर्स में करना लाभदायक रहेगा।

धन प्राप्ति जब पाना हो, यह उपाय आजमाए...

अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है। लेकिन यह धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है।

आइए कुछ आसान टिप्स अपना कर पाएं मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और हो जाए धन-दौलत से समृद्ध...

- लाल धागे में सातमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से धन की प्राप्ति होती है।
- सवा पांच किलो आटा एवं सवा किलो गुड़ लें। दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। तीन गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त होती है।
- ॐ श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः। इस मंत्र की कमलगट्टे की माला से प्रतिदिन जप करने से ऋणमुक्ति होती है।
- मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत (तेल का दीपक) प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दें।

हर बाधा दूर करते हैं श्रीगणेश

प्रथम पूज्य श्रीगणेश का महत्व

प्राचीन समय में हल्दी को गणेश जी की मूर्ति के रूप में पूजा जाता था। हल्दी को मंगलकारी, धन व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। जिस देवता की स्तुति इन शब्दों से की जाती हो, ऐसे पूजनीय रिद्धि-सिद्धि के स्वामी विघ्नहर्ता के जप में हर शुभ मांगलिक कार्य व पूजन में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भालचंद्र यानी श्रीगणेश जी वैवाहिक कार्यों में भी सर्वप्रथम न सिर्फ पूजनीय हैं, अपितु वैवाहिक निमंत्रणों में निमंत्रित किए जाने वाले प्रथम अतिथि भी हैं।

समस्त मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजनीय होने व हर विघ्न और कष्ट को दूर करने की उनकी महत्ता के कारण ही मंगलमूर्ति भी कहे जाते हैं।

यह माना जाता है कि श्रीगणेश जी समस्त दिशाओं में उपस्थित हैं एवं उनके पूजन के साथ शुरू किया गया कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है। अत: सबसे पहले उनकी स्तुति व पूजन कर कार्य शुरू किए जाते हैं। चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो अथवा गृह प्रवेश सभी में श्रीगणेश जी को याद किया जाता है।

यहां तक कि वैवाहिक व अन्य मांगलिक कार्यों के विभिन्न चित्र सर्वप्रथम अंकित किए जाते हैं अथवा उनकी स्तुति से निमंत्रण-पत्र का आरंभ होता है।

हमारे समाज में प्राचीन समय से यह मान्यता रही है कि श्रीगणेश जी के पूजन से शुरू किए गए कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आती और कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। श्रीगणेश को समस्त गणों का अधिपति माना जाता है और इसी वजह से वे गणपति के नाम से भी जाने जाते हैं।

गणेश जी के मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजन को लेकर यह कथा प्रचलित है कि एक बार समस्त देवी-देवताओं को पृथ्वी का चक्कर लगाने को कहा गया, किंतु श्रीगणेश जी अपने भारी शरीर व छोटे से वाहन मूषक के कारण दुविधा में थे कि वे चक्कर कैसे पूर्ण करें। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए माता-पिता पार्वती व शिवजी की परिक्रमा कर ली और सभी के पूछने पर कारण बताया कि माता-पिता तो समस्त संसार के तुल्य हैं।

वे ब्रह्मा के सहायक हैं, अत: उनकी पूजा का विशेष महत्व है। प्राचीन समय में हल्दी को गणेश जी को मूर्ति स्वरूप पूजा जाता था। गणेश जी की उपस्थिति ओंमकार में मानी जाती है।

ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के शुभागमन के साथ सारी बाधाएं खुद-ब-खुद खत्म हो जाती हैं। श्रीगणेश जी सभी का कल्याण करने वाले माने जाते हैं।

वास्तुदोष से बचने के कुछ खास उपाय

वास्तुदोष से बचाएंगे ये उपाय...

अगर आप स्थानाभाव की वजह से रसोईघर को स्टोर अथवा भंडारण कक्ष के रूप में इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्वी दीवार के पास के स्थान का उपयोग करें। चूल्हा या गैस आग्नेय कोण में ही रखें।

- वास्तुदोष से बचने के लिए ध्यान रखें कि दरवाजे व खिड़कियों की संख्या विषम न होने पाएं। इनकी संख्या सम यानी 2, 4, 6, 8 आदि रखें।
- घर में आंगन मध्य में ऊंचा तथा चारों ओर से नीचा होना चाहिए। यदि आपका आंगन वास्तु के अनुरूप न हो, तो उसे फौरन बताए गए तरीके से पूर्ण करवा लें। ध्यान रखें आंगन मध्य में नीचा व चारों ओर ऊंचा भूलकर भी न रखें।
- कोई भूखंड उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तृत हो तथा भवन का निर्माण उत्तरी भाग में हुआ हो तथा भूखंड का दक्षिणी भाग खाली पड़ा हो तो वास्तु में यह स्थिति अत्यंत दोषपूर्ण होती है।
- इस दोषपूर्ण स्थिति के चलते भूस्वामी को कष्टों तथा परेशानियों को झेलना पड़ता है। भूस्वामी को व्यापार में तथा कारोबार में हानि होती है। परिवार में तनाव का माहौल बना रहता है।
- इस स्थिति में वास्तु दोष से बचने के लिए भवन के दक्षिण-पश्चिम कोण यानी नैऋत्य कोण में एक आउट हाउस को मुख्य भवन से ऊंचा बनवाएं और उसके फर्श को भी भवन के फर्श से ऊंचा रखें। आउट हाउस के दक्षिण या पश्चिम दिशा में कोई भी द्वार न रखें।
- कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुख्य द्वार के ठीक सामने अंदर कोई दीवार हो। पर फिर भी उस पर आईना न लगाएं और दीवार पर ऊपर से नीचे तक गहराई का आभास देने वाला कोई प्राकृतिक दृश्य चित्र लगाएं। यह जंगल में दूर-दूर तक दिखाई देने वाली सड़क का चित्र भी हो सकता है।
- मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ आईना लगाना गलत है। ऐसा करने पर घर के अंदर प्रवेश करने वाली ऊर्जा परावर्तित होकर द्वार से बाहर निकल जाती है।

खांड के खिलौने

एक गृहस्थ खांड के तीन खिलौने लाया जो कि तीन साधुओं की मूर्तियां थीं। संयोगवश उसके यहां तीन अतिथि साधु भोजन करने आए। गृहस्थ ने उन्हें बड़ी श्रद्धा से बिठाया। इतने ही में गृहस्थ का छोटा लड़का आया और वह उन खिलौनों के बारे में पूछने लगा- 'यह क्या है, पिता जी।' गृहस्थ बोला 'यह साधु है।' बालक ने पूछा, 'इनका क्या होगा?' गृहस्थ ने कहा- 'इन्हें खाएंगे।' लड़का बोला, 'कब। गृहस्थ बोला- 'पहले इन साधुओं को भोजन कराकर हम खाना खा लें, फिर एक-एक तीनों खा लेंगे।'

गृहस्थ तो इस प्रकार अपने बालक को उन खांड के खिलौनों के बारे में बतला रहा था, उधर साधुओं ने समझा कि यह बातचीत उनके बारे में चल रही है। यह समझकर साधु उसके यहां से भागे। गृहस्थ को बड़ा अचरज हुआ। वह उनके पीछे भागा। वे लोग थककर एक जगह रुके, तो गृहस्थ ने उनके भागने का कारण पूछा।

साधुओं ने कहा कि तुम हमें मार डालना चाहते थे, हम तुम्हारी सब बात सुन रहे थे। गृहस्थ ने कहा- 'महाराज मैं तो बालक से खांड के खिलौनों के बारे में बातचीत कर रहा था।'

तब साधुओं की समझ में आया और वे वापस उसके घर गए और भोजन किया। मन की दुर्बलता से लोग ऐसे ही डरे रहते हैं जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है।

धन कमाने का विशेष महीना कार्तिक

कार्तिक में करें श्रीकृष्ण, तुलसी और लक्ष्मी पूजन

भगवान श्रीकृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक विशेष प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास को पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। स्नान, दीपदान एवं तुलसी की पूजा विशेष फलदायी है।

इस संदर्भ में स्कंद पुराण में कहा गया है :-

मासनां कार्तिक: श्रेष्ठोदेवानांमधुसूदन:।
तीर्थं नारायणाख्यंहि त्रितयंदुर्लभंकलौ।।

अर्थात मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलियुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। स्कंद तथा पद्म पुराण में यह मास धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाला बताया गया है।

राधा-दामोदर मास : भविष्य पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण को राधा से कुंज में मिलने आने में विलंब हो गया। तब राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्रीकृष्ण को लताओं की रस्सी बनाकर बांध दिया। दरअसल माता यशोदा ने कान्हा को किसी पर्व के कारण घर से निकलने नहीं दिया था। जब राधा को वस्तुस्थिति का बोध हुआ तो वे लज्जित हो गईं। उन्होंने क्षमा-याचना कर दामोदर श्रीकृष्ण को बंधनमुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास श्रीराधा-दामोदर मास भी कहलाता है।

सावन-भादो की वर्षा के बाद घरों पर छप्पर छवाने, लीपना-पोतना, नए पौधे लगाना और लक्ष्मी पूजा की तैयारी करना आरंभ हो जाता है। दिवाली के आने का आभास कार्तिक मास के लगते ही हो जाता है।

गोपाष्टमी पर गौ की पूजा, आंवला नवमी पर आंवला पूजन, देवउठनी एकादशी और माह की अंतिम तिथि कार्तिक पूर्णिमा है।

इस दौरान उज्जैन के राजाधिराज महाकाल की दो सवारी कार्तिक मास में निकलेगी। चातुर्मास की समाप्ति होगी तो बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन भी होगा।

इस माह करवा चौथ, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आदि तीज-त्योहार पड़ेंगे। साथ ही कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को सजाया-संवारा जाएगा व भगवान शालिग्राम का पूजन होगा।

इसलिए कहा जाता है कि कृष्णप्रियो हि कार्तिक:, कार्तिक: कृष्णवल्लभ:। कार्तिक में तुलसी की पूजा विशेष फलदायी होती है।

कार्तिक में दीपदान करने से पाप नष्ट होते हैं। इस मास में धन की देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। धन से संबंधित विशेष आराधना व उपासना, तंत्र-मंत्र-यंत्र सब इसी माह करना चाहिए।

देवालय, नदी किनारे, तुलसी के समक्ष एवं शयन कक्ष में जो दीप लगाता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। धन, आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। अंधकार दूर होकर जीवन प्रकाशमान होता है।

भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के निकट दीपक जलाने से अमिट फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य पुण्य का भागी बनता है और उसे लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है।

फेंगशुई प्रोडक्ट

ड्रैगन विंड चाइम

फेंगशुई में विंड चाइम का काफी महत्व है लेकिन 9 रॉड वाले ड्रैगन पर लटके विंड चाइम को और भी ज्यादा महत्ता दी गई है। इसकी 9 रॉड को 9वें सितारे की शक्ति प्रदान करने वाला मानते हैं। विंड चाइम्स को मैजिक बेल्स भी कहते हैं। इसे फेंगशुई के दोषों को दूर करने वाला माना जाता है। ड्रैगन विंड चाइम दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला तो यह मधुर ध्वनि के जरिए जीवन में उमंग लाता है और दूसरा यह नकारात्मक 'ची' को भी ऊर्जावान व सकारात्मक 'ची' में तब्दील करता है। इससे इसके धारक को सौभाग्य प्राप्त होता है। विंड चाइम पर ड्रैगन का बना होना शक्ति व सुरक्षा का भी सूचक है। विंड चाइम अधिकतर कॉपर, तांबे, ब्रास और स्टील के बने होते हैं। इन्हें घर के मैटल कॉनर्स में रखा जाता है, जैसे पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा। लकड़ी या बैंबू से बने विंड चाइम को पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखते हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में सेरेमिक विंड चाइम्स रखे जाते हैं, जो प्रेम और रोमांस के लिए बेहतर माने जाते हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में विंड चाइम को रखने से ज्ञान में बढ़ोत्तरी और घर के बीचों-बीच इसे रखने से पूरे परिवार का भला और कल्याण होता है। इसलिए धातु के विंड चाइम को रखना इस वर्ष के लिए बेहतर और सुखकारक होगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मायावती ने अपने समधी को पार्टी से फिर किया आउट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में बड़े संगठनात्मक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है. पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कड़ा कदम उठाते हुए अपने समधी और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया. उनके साथ बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया. निष्कासन से पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस ले लिया था. इसके बाद पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी आधिकारिक बयान में दोनों नेताओं को निष्कासित किए जाने की घोषणा की गई. इससे पहले अशोक सिद्धार्थ को बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2025 में भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था. मायावती ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत उम्मीदवारों के चयन का अधिकार पूरी तरह उनके पास रहेगा।

कावेरी जल विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद कई दशकों से चला आ रहा है. हाल ही में कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ष्ठख्ख ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह कर्नाटक सरकार को तुरंत तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दें. वहीं, इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार भी सक्रिय हो गई है और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाई. ताजा विवाद कर्नाटक द्वारा कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर हो रहा है. दरअसल, 28 जुलाई को सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगले 15 दिनों तक हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े।

बांग्लादेश के मदरसों में तैयार किए जा रहे जिहादी

नईदिल्ली। विवादास्पद लेखिका तसलीमा नसरीन ने रविवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने ममता के करीबी और कवि जय गोस्वामी के अपमान पर दुख जताया. इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हालात, समान नागरिक संहिता और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अपनी बेबाक राय दी. तसलीमा नसरीन ने कार्यक्रम के दौरान कवि जय गोस्वामी के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा. यह सिर्फ जय गोस्वामी का अपमान नहीं था, बल्कि मेरा भी अपमान था. मैंने ही उन्हें मंच पर बुलाया था. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की है. राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हर किसी को अपनी बात रखने का हक है. उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही जय गोस्वामी के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगी।

चंपत राय और अनिल मिश्रा से दोबारा होगी पूछताछ

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी नई एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस मामले की जांच अब सिर्फ गिरफ्तार हुए आरोपियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी आंच मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच रही है. जानकारी के मुताबिक, जांच टीम अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दोबारा पूछताछ करने की तैयारी कर रही है. पुलिस और जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दान पेटियों से पैसों का हेरफेर मुमकिन कैसे हुआ? एसआईटी ने इस मामले में सिर्फ आठ मुख्य आरोपियों पर ही शिकंजा नहीं कसा है, बल्कि 200 से भी ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए हैं. इन सभी लोगों को अलग-अलग तारीखों पर बुलाकर टीम पूछताछ कर रही है।

पीओके में शांति मार्च के दौरान धमाका, 14 मरे

नईदिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में रविवार को शांति मार्च के दौरान बड़ा धमाका हुआ. काबल टाउन में पुलिस स्टेशन के पास हुए इस विस्फोट में 5 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी मलकंद के अनुसार, शुरुआती जांच में यह आत्मघाती हमला प्रतीत हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, हमले का मुख्य निशाना पाकिस्तानी पुलिसबल था. यह मार्च स्थानीय आदिवासी परिषद स्वात अमन जिरगा ने इलाके में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के विरोध और शांति बहाली की मांग को लेकर निकाला था. मार्च के दौरान अचानक हुए धमाके से अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल भेजा. सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, घायलों की हालत गंभीर होने से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

बारिश से देशभर में भारी तबाही

गुजरात में डूबी सड़कें-अस्पताल, हिमाचल में 102 रास्ते बंद

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केरलम, गुजरात और हिमाचल में सबसे ज्यादा असर है, जबकि राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है।

देश के कई हिस्सों में मानसून लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कहीं लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड ने सड़कें बंद कर दी हैं। सबसे ज्यादा असर केरलम में देखने को मिला है, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह मानने की अपील की गई है। केरलम में बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, आठ लोग लापता हैं और 13 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 209 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 5,792 लोगों को सुरक्षित ठहराया गया है। बारिश की वजह से 27 घर पूरी तरह ढह गए, जबकि 196 मकानों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने कहा है कि जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है या जिनके घर और रोजी-रोटी का नुकसान हुआ है, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इसके अलावा, घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। हालांकि, कई इलाकों में बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राहत अभियान में स्थानीय प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जिन जगहों से पानी उतर चुका है, वहां सफाई का काम शुरू हो गया है।

केरलम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, शनिवार को कुछ इलाकों में 320 मिमी तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा पानी कन्नूर के अय्यनकुन्नू इलाके में बरसा। पथानामथिट्टा, इडुक्की, वायनाड, कोट्टायम, कोझिकोड, कन्नूर के कई निचले हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो गए। घरों में पानी घुसने के बाद लोगों को नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। अकेले पथानामथिट्टा जिले के 25 गांवों में करीब 40 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश थमने से कई बांधों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हालांकि कुछ बिजली परियोजनाओं वाले जलाशयों में जलस्तर अब भी रेड अलर्ट के निशान पर बना हुआ है। म

गुजरात और हिमाचल में भी मुश्किलें कम नहीं

पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजरात के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। नवसारी, सूरत, भरूच, खेड़ा, डांग, भावनगर, नर्मदा, महीसागर में हालात काफी खराब हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। नडियाद शहर में कॉलोनियों के अंदर चार-चार फीट तक पानी जमा हो चुका है। दुकानों से लेकर गाड़ियों तक, सब कुछ पानी की चपेट में है। अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों पर पानी भरने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। लोग वहीं फंसने को मजबूर हैं। डांग और नवसारी में बहने वाली अंबिका, पूर्णा नदियां पूरे उफान पर हैं। पूर्णा नदी का बहाव इतना तेज है कि गोदड़िया पुल पूरी तरह डूब चुका है, पानी उसके ऊपर से बह रहा है। खतरा बढ़ता देख आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी राहत के आसार फिलहाल कम हैं। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बाद 102 सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा असर मंडी, कुल्लू और शिमला में देखा गया है। इसके अलावा 28 पेयजल योजनाएं और 11 बिजली ट्रांसफॉर्मर भी प्रभावित हुए हैं। लोगों से पहाड़ी इलाकों में बिना जरूरत यात्रा नहीं करने की अपील की गई है।

राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश में अलर्ट

केरल और गुजरात के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी मौसम का मिजाज लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। सलूंबर में सबसे ज्यादा 67 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा, इसलिए बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं, झारखंड में भी 6 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। हजारीबाग, पलामू, चतरा, रांची, गुमला, खूंटी, देवघर, दुमका, पाकुड़ और पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में अलग-अलग दिन भारी बारिश हो सकती है। लोगों से खराब मौसम में खुले स्थानों पर नहीं जाने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है। जबकि, आंध्र प्रदेश में भी रविवार और सोमवार को तटीय इलाकों, यनम और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है। कुछ जगह हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है।

देशभर में एक जैसा नहीं है मानसून का हाल

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस बार मानसून पूरे देश में एक जैसा असर नहीं दिखा रहा है। पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत और गंगा के मैदानी इलाकों में अभी भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 4 जून से अब तक देश में सामान्य 446।3 मिमी के मुकाबले 395।5 मिमी बारिश हुई है, यानी अब भी करीब 11 फीसदी की कमी बनी हुई है।

ई20 से परेशान हैं मैकेनिक और वाहन मालिक: जयराम रमेश

नई दिल्ली। देशभर में ई20 पेट्रोल यानी 20 फीसदी इथेनॉल मिले ईंधन की बिक्री को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि बिना पुख्ता डाटा के यह ईंधन देश की जनता पर थोपा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 29 जुलाई को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संसद में दिए जवाब से जनता का भ्रम दूर नहीं हुआ, बल्कि नए सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार दावा कर रही है कि ई20 पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर उपभोक्ता और मैकेनिक दोनों परेशान हैं, बेबस हैं।

जयराम रमेश ने आगे कहा कि जून 2026 में 2023 से पहले के 44,000 वाहन चालकों के स्वतंत्र सर्वे में ई20 से गाड़ियों में भारी नुकसान की बात सामने आई। सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इंजन खराब होने की शिकायतों को बकवास कहकर खारिज कर दिया था।

जयराम रमेश ने कहा कि नीती आयोग की 2021 की रिपोर्ट खुद मानती है कि ई20 से ई10 क्षमता वाले वाहनों के रबर पुर्जों को तेजी से नुकसान पहुंचता है। जुलाई 2026 की ARAI रिपोर्ट के अनुसार ई20 से वाहनों के फ्यूल टैंक और धातु के अंदरूनी पुर्जों में जंग लगने का खतरा है। ई20 से पुरानी 4-व्हीलर का माइलेज 6-7%, 2-व्हीलर का 3-4% और ई20-कम्पेटीबल नई गाड़ियों का माइलेज भी 1-2% तक गिरता है।

जयराम रमेश के मुताबिक, महीनों से देशभर के वाहन चालक और मैकेनिक ई20 पेट्रोल को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। गाड़ियों के माइलेज में लगातार कमी देखी जा रही है। इंजन के प्रदर्शन में गिरावट, ठंड में कोल्ड-स्टार्ट की समस्या और समय से पहले इंजन घिसने की शिकायतें आ रही हैं। 2023 से पहले बनी गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्टर जाम हो रहे हैं, फ्यूल पाइप में जंग लग रही है और रबर सील, होज पाइप, गस्केट गल रहे हैं।

आम उपभोक्ताओं के पास ई20 खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। जयराम रमेश का कहना है कि सरकार के अपने ही दस्तावेज श्व20 से होने वाले नुकसान को स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद सरकार सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। बार-बार झूठ बोल रही है। टेस्ट रिपोर्ट में पैसेंजर व्हीकल्स के इंजन फेल होने तक की बातें सामने आई हैं। देश में जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

ई20 ईंधन के विरोध में नागपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

नागपुर। नागपुर पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर आवास की ओर मार्च कर रहे भारतीय यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। मेहुल आडवाणी जैसे स्थानीय नेताओं की अगुवाई में हुए इस विरोध-प्रदर्शन का मुख्य कारण ई20 (20% एथेनॉल-मिश्रित) पेट्रोल को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ जनता का असंतोष था। यूथ कांग्रेस नेता मेहुल आडवाणी ने कहा, हम हम पर थोपे जा रहे ई-20 का विरोध करते हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि ई20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंच रहा है और माइलेज में गिरावट आ रही है। विशेष रूप से पुराने वाहनों के लिए इसे हानिकारक बताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि उपभोक्ताओं को बिना इथेनॉल वाले सामान्य पेट्रोल को भी खरीदने का स्पष्ट विकल्प मिलना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर

मुंबई। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनके बाएं घुटने में लगी चोट से वह अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में चयन समिति ने उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया है।

आकिब नबी को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली है। जम्मू-कश्मीर के इस युवा तेज गेंदबाज ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 104 विकेट लिए हैं। 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने 60 विकेट चटकाए और जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

आकिब नबी हाल ही में इंडिया ए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर भी गए थे। वहां उन्होंने दो प्रथम श्रेणी मैचों में छह विकेट अपने नाम किए थे। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम अब सीनियर भारतीय टीम में चयन के रूप में मिला है।

आकिब ने अभी तक 43 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 162 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 24 रन देकर सात विकेट रहा है। उन्होंने 16 बार पारी में पांच विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा आकिब 36 लिस्ट-ए और 39 टी20 भी खेल चुके हैं। लिस्ट-ए में उन्होंने 56 विकेट और टी20 में 43 विकेट चटकाए हैं। लिस्ट-ए में आकिब का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 39 रन देकर चार विकेट है, जबकि टी20 में यह 16 रन देकर चार विकेट है।

आकिब ने प्रथम श्रेणी में 18.84 की औसत से 999 रन भी बनाए हैं। इनमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट-ए में आकिब के नाम 27.23 की औसत से 572 रन हैं। इनमें एक शतक शामिल है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 544 अंक उछला निफ्टी 24,774 पर बंद

नईदिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई, जिससे भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन भी तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.70 फीसदी की बढ़त के साथ 78,639 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी50 भी बढ़त के साथ 24,774 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी50 में इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर रहे। वहीं, व्यापक बाजार में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 1.21 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 1.29 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं, निफ्टी मीडिया दिन का सबसे कमजोर सेक्टर रहा।

जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिरकर 53.5 पर

नईदिल्ली। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार जुलाई में धीमी पड़ गई। नए ऑर्डर मिलने की गति कम हुई, कच्चे माल की खरीद घटी और रोजगार में भी सुस्ती देखने को मिली। इसके चलते फैक्ट्री गतिविधियां करीब पांच साल की सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ीं। यह जानकारी सोमवार को जारी एक निजी सर्वे में सामने आई। एचएसबीएस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जुलाई में घटकर 53.5 पर आ गया, जबकि जून में यह 54.2 था। यह अगस्त 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। साथ ही यह इंडेक्स अपने लंबे समय के औसत 54.2 से भी नीचे रहा। पीएमआई में 50 से ऊपर का आंकड़ा मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेत देता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सस्ता किया होम लोन

नईदिल्ली। घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज दरों में कटौती की है। अब बैंक 7% सालाना शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही बैंक ने प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह माफ कर दी है, जिससे नए ग्राहकों की शुरुआती लागत कम हो जाएगी। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए शुरू की गई विशेष पेशकश मानसून धमाका के तहत दी जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार, 750 से 799 के बीच क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को 7.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा। 800 या उससे अधिक क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर 7% सालाना से शुरू होगी। इस ऑफर के तहत होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह खत्म कर दी है।

तीन तेल कंपनियों ने बिगाड़ा 211 कंपनियों का रिजल्ट

नईदिल्ली। जून तिमाही के नतीजों की पहली तस्वीर बहुत मजबूत नहीं दिखती। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के दायरे में आने वाली 211 कंपनियों का कुल मुनाफा सालाना आधार पर सिर्फ 2 फीसदी बढ़ा। लेकिन इस आंकड़े के पीछे बड़ी कहानी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की है। अगर इन कंपनियों को हटा दें, तो बाकी कंपनियों का मुनाफा 17 फीसदी बढ़ा। यानी तिमाही नतीजों की असली हालत ऊपर से दिखने वाले 2 फीसदी के आंकड़े से कहीं बेहतर रही। रिपोर्ट के मुताबिक, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसी को जून तिमाही में कुल मिलाकर करीब 18,100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एक साल पहले इसी तिमाही में इन कंपनियों ने करीब 16,200 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

आरबीआई की 'इंतजार करो और देखो' की रणनीति, ब्याज दरें स्थिर रहने के आसार

तमाल बंद्योपाध्याय

वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों के लिए पिछला पखवाड़ा घटनापूर्ण रहा। शुक्रवार को बैंक ऑफ जापान ने अपनी नीतिगत ब्याज दर को 1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। उसने मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ने की स्थिति में उधार लागत बढ़ाने की अपनी तत्परता दोहराई। उसकी नीतिगत बैठक में मध्य जून में बढ़ोतरी कर 1 प्रतिशत करने के बावजूद मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में 8-1 से मतदान हुआ। आखिरी बार 1 प्रतिशत का स्तर 1995 में देखा गया था।

इससे एक दिन पहले, बैंक ऑफ इंगलैंड ने भी उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। उसकी मौद्रिक नीति समिति ने 6-3 के मत से दरों को 3.75 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया। बैंक ऑफ इंगलैंड ने चार बार ब्याज दरों में कटौती करने के बाद दिसंबर 2025 से ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने पिछले सप्ताह की शुरुआत में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा, लेकिन फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के तीन सदस्यों ने कहा कि वे एक चौथाई प्रतिशत की वृद्धि पसंद करते। सितंबर 2016 के बाद पहली बार हुआ है जब तीन नीति निर्माताओं ने दिशा के बारे में समान दृष्टिकोण के साथ असहमति व्यक्त की थी। पिछले सप्ताह, 23 जुलाई को, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में एक चौथाई प्रतिशत अंक की वृद्धि की थी। तो इस सप्ताह हम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसकी छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक सोमवार को शुरू होगी।

सबसे पहले, देखें कि 5 जून को पिछली नीतिगत घोषणा के बाद से चीजें कैसे बदल गई हैं, जिसमें दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया था, मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाया गया था और वृद्धि के अनुमान को कम किया गया था।

10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड, जो 5 जून को 6.975 प्रतिशत पर बंद हुई थी, 6 जुलाई को गिरकर 6.685 प्रतिशत पर आ गई, जो हाल के समय में इसका सबसे निचला स्तर है। पिछले शुक्रवार को यह 6.83 प्रतिशत पर बंद हुई थी।

5 जून को रुपया 94.94 डॉलर प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अगले दो हफ्तों में 18 जून तक, यह बढ़कर 94.33 डॉलर हो गया, जो विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आरबीआई की बहुआयामी रणनीति से प्रेरित था। पिछले शुक्रवार को यह 95.39 डॉलर प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो 23 जुलाई को 96.57 डॉलर तक पहुंचने के बाद से काफी मजबूत हुआ है। शनिवार को आरबीआई ने कहा कि विदेशी पूंजी आकर्षित करने की अवधि समाप्त होने के बाद से अब तक 40.82 अरब डॉलर का निवेश हुआ है।

आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जो जून के पहले सप्ताह में 543.4 अरब डॉलर थी, 24 जुलाई तक बढ़कर 555.9 अरब डॉलर हो गई। हालांकि, इस अवधि के दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 682 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित रहा।

विदेशी मुद्रा का प्रवाह भंडार में क्यों नहीं दिख रहा है? इसके चार कारण हो सकते हैं ङ्क आरबीआई हाजिर बाजार में डॉलर बेच रहा है; यह फॉरवर्ड बुक (खरीद/बिक्री की स्थिति) को परिपक्व होने दे रहा है, रोलओवर नहीं कर रहा है और ग्राहक मौजूदा एफसीएनआर(बी)/एनआरई खातों से निकासी कर नई एफसीएनआर(बी) योजना के माध्यम से पैसा वापस डाल रहे हैं। हमें एफसीएनआर(बी) में नया प्रवाह तो दिख रहा है, लेकिन मौजूदा भंडार से निकासी नहीं। अंत में, सोने की कीमत में गिरावट भी एक कारण है। 5 जून को सोने का भंडार 114.57 अरब डॉलर का था, 24 जुलाई तक यह 103 अरब डॉलर गिर गया, जिससे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि बेअसर हो गई। एक सप्ताह पहले इसमें और भी अधिक गिरावट आई थी। इस पृष्ठभूमि में, मुझे उम्मीद है कि भारत के केंद्रीय बैंक की दर निर्धारण संस्था यथास्थिति बनाए रखेगी। नीतिगत दर में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जा सकता है।

प्रोजेक्ट सहारा के तहत 3.58 करोड़ रुपये के सहायक उपकरणों का वितरण

पीएम मोदी ने दिव्यांग शब्द देकर सम्मान और आत्मगौरव का नया भाव दिया : सीएम साय

रायपुर। किसी भी संवेदनशील और विकसित समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने का अधिकार मिले। दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी प्रतिभा, क्षमता तथा आत्मविश्वास को सही अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसी सोच के साथ दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक अपना योगदान दे सकें।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रोजेक्ट %सहारा% के अंतर्गत दिव्यांगजन

सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के प्रति देश की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने केवल कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें दिव्यांग कहकर सम्मान और आत्मगौरव का नया भाव भी दिया। यह परिवर्तन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि समाज की सोच और दृष्टिकोण का परिवर्तन है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासके मंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल अधोसंरचना का विकास केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे सामाजिक और जनहितकारी आयोजनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड, कृत्रिम हाथ-पैर, वैशाखी, वॉकिंग स्टिक तथा अन्य आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने हितग्राहियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि ये उपकरण केवल सहायता सामग्री नहीं हैं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की नई शुरुआत हैं। इनकी सहायता से दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार, आवागमन और दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे तथा समाज की मुख्यधारा से और अधिक मजबूती से जुड़ पाएंगे।मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेशवासियों को सावन माह के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देती है तथा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना हम सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर जिले में विशेष अभियान चलाकर दिव्यांगजनों की व्यापक स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1600 से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान की गई।

कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाली ज्ञानेश्वरी डीएसपी पद पर पदोन्नति

30 लाख की प्रोत्साहन राशि

रायपुर। आज मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की रजत पदक विजेता, राजनांदगांव की हमारी प्रतिभाशाली बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी ने पूरे छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि हमारी बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त उदाहरण है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में 30 लाख की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को हरसंभव अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वास है कि ज्ञानेश्वरी आने वाले समय में भी भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के बल पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की है। उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी इस बेटी पर गर्व है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी उपलब्धि का सम्मान हो और प्रदेश के अन्य खिलाड़ी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित हों। सीएम ने कहा कि ग्लासगो रवाना होने से पहले उन्हें ज्ञानेश्वरी से मिलने का अवसर मिला था।

'नशा मुक्त युवा, के कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल हुए शामिल

रायपुर। ब्रह्माकुमारीज़, अंबिकापुर द्वारा आयोजित 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान' कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने सहभागिता करते हुए युवाओं से नशामुक्त, अनुशासित और संस्कारयुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत आधार स्वस्थ, जागरूक, चरित्रवान और आत्मविश्वासी युवा है। जब युवा सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रसेवा की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित भारत का संकल्प साकार होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान' केवल नशे के विरुद्ध जनजागरण का अभियान नहीं, बल्कि देश के भविष्य को सशक्त बनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। यह अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली, आत्मअनुशासन, सकारात्मक विचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता केवल आर्थिक विकास की नहीं, बल्कि ऐसे समाज के निर्माण की है, जहां युवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हों। नशा व्यक्ति की प्रतिभा, परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति तीनों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक युवा का यह दायित्व है कि वह स्वयं नशे से दूर रहे और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करे।

श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत की युवा शक्ति विश्व की सबसे बड़ी ताकत है।

प्रदेश स्तरीय भव्य कलश वन्दन अभियान कार्यक्रम आज, मुख्यमंत्री साय रहेंगे उपस्थित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के निमित्त आयोजित प्रदेशस्तरीय भव्य कलश वन्दन अभियान के तहत वाराणसी से पवित्र माटी व जलयुक्त कलश के वितरण का कार्यक्रम कल 4 अगस्त को रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित पं. दीनदयाल ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय के साथ ही प्रदेश के साधु-संत एवं विभिन्न समाजों के समाज प्रमुख उपस्थित रहेंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संत रविदास जयंती कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अखिलेश सोनी ने बताया कि संत रविदास के समरस समाज के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ये पवित्र कलश में प्रदेश के सभी जिलों में पहुँचेंगे। संत रविदास की 650वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी व जल का स्वागत अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में निरंतर चलाया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश में समरसता और सद्भाव का वातावरण निर्मित हो सके। श्री सोनी ने बताया कि भाजपा द्वारा भव्य कलश वन्दन अभियान के लिए 36 रथ बनाए गए हैं जो प्रदेशस्तरीय भव्य कलश वन्दन अभियान कार्यक्रम के पश्चात भाजपा के सभी संगठनात्मक जिलों में पहुँचेंगे। अगले चरण में जिलास्तरीय कलश वन्दन कार्यक्रम होगा जिसमें जिलों की मण्डल इकाइयों को ये कलश वितरित किए जाएंगे जो मण्डल के प्रमुख गाँवों में जाएंगे और विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात मंदिरों में ये कलश रखे जाएंगे।

भाजपा सरकार ढाई साल में ही आलोकप्रिय हो गयी: बैज

रायपुर। भाजपा सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में जनता का भरोसा खो दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार के खिलाफ चौतरफा आक्रोश है। मोदी की गारंटी के नाम पर जनता का मत हासिल किया। ढाई साल में एक भी मोदी की गारंटी पूरा नहीं किया। सरकार से प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। किसान नाराज है, युवा नाराज है, सरकारी भर्तियां बंद है, जो भर्तियां हुई है उसमें भ्रष्टाचार किया गया। फारेस्ट आरक्षक भर्ती, पुलिस आरक्षक भर्ती, आरआई भर्ती सभी जगह आरक्षक भ्रष्टाचार हो रहा। आदिवासियों किसानों की जमीने जबरिया उद्योगो और खदानों के लिये अधिग्रहित की जा रही है। विरोध करने पर लाठियां चालाई जा रही है, महिलाएं निराश है, महतारी वंदन के नाम पर उनसे धोखा दिया गया। प्रदेश में 1.25

लाख से अधिक विवाहित महिलाएं है, महतारी वंदन की राशि 67 लाख महिलाओं को दे रहे है। कर्मचारी नाराज है, सरकार ने उनको भी धोखा दिया। अनियमित कर्मचारियो को नियमित करने का वादा पूरा नहीं किया। बिजली के दाम बढ़ाने, भूमि के गाइडलाइन के रेट बढ़ाने, 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री बंद करने से जनता नाराज है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सरकार के ढाई साल के कार्यकाल से खुश हो।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल में छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। साय सरकार की उपलब्धि के नाम पर पिछली सरकार की योजनायें बंद करना मात्र है। साय सरकार ने जनता के हित में चलाई जाने वाली योजनओं को दुर्भावनापूर्ण बंद किया। 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिया, राजीव मितान योजना, गोधन न्याय योजना, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना, बेरोजगारी भत्ता, रीपा, मुख्यमंत्री कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी, महिला समूहों की ऋण माफी, सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि, सीएम छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि, कोदो कुटकी रागी खरीदी, नरवा-गरवा-घुरवा बारी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मुख्यमंत्री महतारी दुलार, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, धरसा विकास, शहरी गरीबों को पट्टा एवं आवास, छत्तीसगढ़िया ओलिंपिक, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को बंद किया। यह सरकार दुर्भावना वाली सरकार है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से श्रमिक बच्चों को मिली नई उड़ान

रायपुर। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जिला बीजापुर के विभिन्न विकासखंडों के कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का इस योजना के तहत चयन हुआ है। विकासखंड उसूर के ग्राम बसागुड़ा की छात्रा सान्वी संगम का चयन दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव में हुआ है। वहीं विकासखंड भोपालपटनम के ग्राम गुल्लागुड़ा की छात्रा परिधि कावटी, विकासखंड बीजापुर के ग्राम सागमेटा के छात्र देवांश जनगम तथा ग्राम गुल्लागुड़ा की छात्रा निहारिका नीकुरी का चयन हम एकेडमी, जगदलपुर में हुआ है। विकासखंड भैरमगढ़ के ग्राम छोटे गोगला के छात्र आदित्य कोरसा का चयन भी दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव में हुआ है। चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बताया कि वे श्रमिक परिवार से हैं और सीमित आय के कारण बच्चों को अच्छे निजी विद्यालयों में पढ़ाना उनके लिए संभव नहीं था।

ग्रामीण उद्यमिता का मार्ग है संभागीय सरस मेला: शर्मा

रायपुर। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर चौरा में आयोजित पांच दिवसीय संभागीय सरस मेला का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि संभागीय सरस मेला से ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को एक नई दिशा मिलती है तथा यह आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होता है।सरस मेला में स्वदेशी, प्राकृतिक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी सह विक्रय हेतु संभागीय सरस मेला समूह की दीदियों के लिए सफलता के द्वार खोलेगा। संभागीय सरस मेला के उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग बिसेसर पटेल, गणमान्य नागरिक जिले के अधिकारी गण, स्व सहायता समूह की दीदियों सहित ग्रामीण उपमिले में लगे स्टालों का उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अवलोकन किया तथा महिला समूह से उनके उत्पादन के विषय में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान स्टॉल से खरीदी कर महिला समूह का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें सफल व्यवसाय की शुभकामनाएं दी।

सफर में भटकी बिहार की महिला को मिला नया सहारा

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर संकट में फंसी महिलाओं के लिए भरोसेमंद सहारा बनकर सामने आ रहा है। दंतेवाड़ा जिले में इसका एक संवेदनशील उदाहरण देखने को मिला, जहां बिहार की एक महिला को सुरक्षित आश्रय देकर उसके परिवार से मिलाया गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली श्रीमती सविता देवी अपने मायके से ससुराल जाने के लिए मोतीपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थीं। यात्रा के दौरान वह सो गईं और कई स्टेशनों को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के किरंदुल (जिला दंतेवाड़ा) पहुंच गईं। वहां से वह पैदल निकल पड़ीं और भटकते-भटकते भांसी तक पहुंच गईं। स्थानीय लोगों ने उनकी स्थिति देखकर भांसी थाना को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रूप से सखी वन स्टॉप सेंटर, दंतेवाड़ा में अस्थायी आश्रय दिलाया।सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर और थाना काटी से संपर्क किया। महिला का नाम, पता और फोटो भेजकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई। जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि महिला मुजफ्फरपुर जिले की ही निवासी हैं।इसके बाद महिला के परिवार से संपर्क किया गया और उन्हें पूरी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही उनके पति दंतेवाड़ा पहुंचे।

यूसीसी पर आम नागरिकों और संगठनों से मांगे गए सुझाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता और इसकी रूपरेखा पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति राज्य के निवासियों के व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। समिति ने इस महत्वपूर्ण विषय पर आम नागरिकों और राज्य में कार्यरत विभिन्न संगठनों से सुझाव और अभिमत मांगे हैं। इसमें शासकीय एवं गैर-शासकीय संगठन, सामाजिक समूह एवं समुदाय, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक दल शामिल हैं। इच्छुक नागरिक और संगठन अपने सुझाव 30 सितंबर 2026 या उससे पहले ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in, यूसीसी वेब पोर्टल https://ucc.cgstate.gov.in/ अथवा डाक के माध्यम से समिति को भेज सकते हैं। डाक द्वारा सुझाव कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कक्ष क्रमांक 201, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001 के पते पर भेजे जा सकते हैं। समिति ने सभी संबंधित नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और अभ्यावेदन समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

केजरीवाल के आह्वान पर छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता 4 अगस्त को करेंगे दिल्ली कूच

रायपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनविरोधी ई20 पेट्रोल नीति के खिलाफ 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से भी बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से 50-50 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होंगे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि ई-20 पेट्रोल नीति के कारण देशभर में वाहन मालिकों और आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाहनों में तकनीकी खराबियां, माइलेज में गिरावट और मेंटेनेंस खर्च में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रही है।आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल एक नीति के खिलाफ नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए है। पार्टी का मानना है कि बिना पर्याप्त तैयारी और वैज्ञानिक अध्ययन के लागू की गई श्व20 नीति देश की करोड़ों गाड़ियों और उनके मालिकों के लिए खतरा बन गई है।

'मुस्कुराता बस्तर' कार्यशाला आयोजित

कला के माध्यम से अभिव्यक्ति एक बड़ा हुनर: वनमंत्री कश्यप

120 स्कूली विद्यार्थियों ने वरिष्ठ कार्टूनिस्टों से सीखी कार्टून और कैरिकेचर की बारीकियां

रायपुर। बस्तर की सकारात्मक छवि, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को रचनात्मक कला के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को जगदलपुर के एक निजी होटल में 'मुस्कुराता बस्तर' कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका 'कार्टून वॉच' द्वारा आयोजित इस

कार्यशाला में जिले के 10 विद्यालयों के 120 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि अपनी भावनाओं और विचारों को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करना भी एक विशेष हुनर है। उन्होंने कहा कि कार्टून और कैरिकेचर केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और विकास के सकारात्मक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की सशक्त कला है। इस अवसर पर महापौर श्री संजय पांडेय एवं एमआईसी सदस्य श्री संग्राम सिंह, स्कूलों के शिक्षक एवं विद्यार्थीगण भी उपस्थित रहे। बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने भी कार्यशाला में पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री माधव जोशी और पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार श्री शुभम जिंदे ने लाइव डेमो के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्टून एवं कैरिकेचर निर्माण की तकनीकें सिखाईं। उन्होंने विद्यार्थियों को कला के सामाजिक महत्व, रचनात्मक संभावनाओं तथा रोजगार के अवसरों की भी जानकारी दी। गौरतबल है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर विकास, विश्वास और नई संभावनाओं के साथ नई पहचान बना रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा तथा जनजातीय संस्कृति जैसी धरोहरें बस्तर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिला रही हैं। 'मुस्कुराता बस्तर' कार्यशाला का उद्देश्य इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को कार्टून कला के माध्यम से रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। कार्यशाला में बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मक प्रतिभा से कैनवास पर नए बस्तर की बदलते स्वरूप, विकास और खुशहाली की जीवंत तस्वीर उकेरी। 'कार्टून वॉच' के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना और बस्तर की खूबियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

बिजली की खपत हुई कम, एम ऊर्जा योजना से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

रायपुर। रायपुर सिटी रीजन में जुलाई-2026 के दौरान स्मार्ट मीटरधारी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। स्लैब-वार उपभोग आंकड़ों के अनुसार कुल 3,17,392 स्मार्ट मीटरधारी घरेलू उपभोक्ताओं में से 2,56,471 उपभोक्ता (लगभग 81 प्रतिशत) 400 यूनिट तक बिजली खपत की श्रेणी में रहे हैं।

इससे राज्य सरकार की एम ऊर्जा (मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान) का लाभ अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जून-जुलाई के खपत का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसमें पता चला कि जुलाई 2026 में कुल बिजली खपत 89.38 मिलियन यूनिट (एमयू) रही, जो जून-2026 में दर्ज 131.27 मिलियन यूनिट (एमयू) की तुलना में 31.91 प्रतिशत कम है।

जारी आंकड़ों के अनुसार जून-2026 की तुलना में जुलाई-2026 में कुल स्मार्ट मीटरधारी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 3,17,392 पर स्थिर रही, किंतु उपभोक्ताओं के स्लैब-वार वितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया गया। 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या जून में 1,96,777 से बढ़कर जुलाई में 2,56,471 हो गई, जो 30.34 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं इस वर्ग की कुल बिजली खपत 41.72 मिलियन यूनिट से घटकर 32.38 मिलियन यूनिट रह गई।इसी प्रकार 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1,20,615 से घटकर 60,921 रह गई, जो 49.49 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। इस वर्ग की कुल बिजली खपत भी 89.55 मिलियन यूनिट से घटकर 57.00 मिलियन यूनिट दर्ज की गई।सर्वाधिक कमी 600 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग में दर्ज की गई। इस श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या में 64.23 प्रतिशत की कमी तथा बिजली खपत में 38.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।विभाग के अनुसार बिजली खपत में यह कमी मुख्यत: दो कारणों से हुई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.